fo"k; lwph — lEikndh; — कमल संदेश

नितिन गडकरी अध्यक्ष निर्वाचित 5

महंगाई

धरना प्रदर्शन......................... 4

नितिन गडकरी का वक्तव्य... 7

लेख

पेशकश के पीछे का सच
ykyÑ".k vMok.kh....... 9

स्वायत्तता का सवाल
txekgu........................ 11

राजनीति से दूर मत भागिए
çHkkr >k........................ 13

पं. दीनदयाल उपाध्याय
fot; idk'k.................. 15

बढ़ती महंगाई लाचार सरकार
vf'ouh egktu............ 17

प्रगति पथ पर मध्यप्रदेश
HkjrpUæ uk;d............ 28

अन्य

प्रत्यक्ष कर संहिता का विरोध.. 18

प्रदेशों से

मध्यप्रदेश............................. 22

छत्तीसगढ़............................ 24

उत्तर प्रदेश......................... 30

सम्पादक

çHkkr >k] lkaln

सम्पादक मंडल

lR;iky

d- d- 'kek

lqtho dqekj flUgk

पृष्ठ संयोजन

/keUæ dk'ky

सम्पर्क

डा. मुकर्जी स्मृति न्यास
पीपी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग
नई दिल्ली–110003
फोन नं. +91(11)–23381428
फैक्स : +91(11)–23387887
सदस्यता हेतु : +91(11)–23005700

सदस्यता शुल्क

वार्षिक 100रु. | त्रिवार्षिक 250रु.

e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का जीवित रहना मृत्यु के समान है, इसमें कोई संशय नहीं। }

-श्रीमद्भागवत गीता

मौत आ नहीं रही और केन्द्र सरकार जीने नहीं दे रही

अपने आप मौत आ नहीं सकती। वहीं जीवित रहने की स्थिति भी धीरे–धीरे समाप्त हो रही है। आम जन की पीड़ा, पता नहीं केन्द्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार क्यों नहीं समझ पा रही? किसानों की आत्महत्याओं की एक नहीं अनेक घटनाएं देश में घटती रहती है। वहीं अब नागरिकों द्वारा परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या की घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं। नागरिकों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं की तह में जाने के बाद पता चल रहा है कि अधिकतर आत्महत्या की घटनाएं आर्थिक तंगी के कारण की जा रही है। 'रोटी' के लिए 'खर्च' न जुटा पाने के कारण आज आम आदमी मौत के मुंह में जाना बेहतर समझ रहा है और इसके बाद भी केन्द्र सरकार का सिर्फ बहस–विलास और आपस में आरोप–प्रत्यारोप के विलास में डूबे रहना कहां का न्याय है? आठ माह बीत गए पर सौ दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली यूपीए सरकार के सौ दिन शायद अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। 61वां गणतंत्र दिवस मनाने वाली जनतंत्र की ऐसी बहाली आजाद भारत में पूर्व में कभी नहीं देखी।

'रोटी–कपड़ा–मकान' उपलब्ध कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी जिस कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की है वह आपसी कलह में डूबी है। कभी–कभी ऐसा लगता है कि 'राजनीति' का मतलब अब सिर्फ सत्ता हथियाना मात्र रह गया। भारतीय राजनीति का मानवीय संवेदनाओं से दूर होते जाना एक खतरनाक संकेत है। कितनी बड़ी विडम्बना है कि सरकार नागरिकों की मौत स्वीकार रही है पर महंगाई कम नहीं कर पा रही उल्टे इस दिशा में कोई पहल भी प्रारम्भ नहीं कर रही।

यह विडम्बना ही है कि आम नागरिकों के लिए चुनी गई कांग्रेसनीत यूपीए सरकार आम नागरिकों को महंगाई की सौगात देकर मौत पसार रही है। भारतीय जनता पार्टी देशभर में आंदोलन की रूपरेखा बना रही है। भाजपा को चाहिए कि जो निजाम जनता को धोखा दे, उस निजाम की धोखेबाजी को जनता के सामने लाना चाहिए। 'जनता' उस पार्टी का पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करती है, जो उसकी लड़ाई के लिए शहादत और बलिदान देने तक लड़ती है।

समस्याओं को लेकर जमीनी संघर्ष की शुरूआत भाजपा को करना

ही होगा। जनता अब उसी के गले में सत्ता की वरमाला डालेगी, जो उसके लिए रात–दिन नहीं बल्कि 'ओव्हरटाईम' के साथ संघर्ष करेगी। संघर्ष भी परिणामकारी करना होगा।

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राजनीतिक प्रोपगंडा में शोध करते हुए पीएचडी प्राप्त करने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि राजनैतिक शगूफेबाजी और मीडिया में बने रहने से आम नागरिकों का दुख–दर्द दूर हो जाएगा। यह उनकी राजनैतिक समझ हो सकती है पर राजनीति की ऐसी समझ नहीं है। एक गम्भीर कार्य राजनीति को कितने उथले और निचले स्तर तक ला सकता है इसका ताजा उदाहरण राहुल गांधी की बचकानी राजनैतिक हरकतों से लगाया जा सकता है।

देश सवाल कर रहा है कि राहुल जी महंगाई को लेकर दौरे क्यों नहीं कर रहे हैं? वे क्यों नहीं जनता के बुनियादी सवालों का जवाब दे रहे हैं? क्या राजनैतिक कार्यकर्ता के नाते यह उनका दायित्व नहीं है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस पूरी तरह सत्ता में आने के लिए उद्योगपतियों के सामने घुटने टेक चुकी है। यही वजह है कि आज वह आम आदमी की बजाय उद्योगपतियों की सुन रही है और शरद पवार की। सुने भी क्यों? चुप रहने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वह सब कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उन लोगों के लिए किया है। यही कारण है कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी मौन है और शरद पवार मंत्री रहते हुए भी गाली खा रहे हैं पर चुप हैं। बहरहाल कुछ भी हो, आम नागरिक महंगाई के कोड़े के भय से बुरी तरह आहत ही नहीं बल्कि मौत को स्वीकार कर रहा है। ■

महंगाई विरोधी धरना–प्रदर्शन

महंगाई के लिए सोनिया, मनमोहन, पवार पूरी तरह से जिम्मेदार: नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार की गलत नीतियों से बेलगाम हुई महंगाई के विरोध में जंग का एलान कर दिया है। गत 10 फरवरी, 2010 को नई दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित महंगाई विरोधी धरना–प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गले में सब्जियों की मालाएं पहने पार्टी कार्यकर्ताओं ने 'चीनी हुई कड़वी और कांग्रेस आई मंहगाई लाई' जैसे नारे लगाए। वे मंहगाई को नियंत्रित नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और कृषि मंत्री शरद पवार के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने धरना को सम्बोधित करते हुए व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा कि शरद पवार देश के कृषि मंत्री नहीं क्रिकेट मंत्री हैं। उन्हें महंगाई की मार झेल रही जनता से ज्यादा आईपीएल की फिक्र है। श्री गडकरी ने कहा कि पीएम को उनके लिए एक अलग क्रिकेट मंत्रालय गठित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंहगाई पवार के लिए वन डे मैच की तरह हो गई है। चीनी के दाम अर्धशतक पार कर चुके हैं और दाल के दाम शतक। पवार इस टीम के कोच हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, सोनिया और पवार की त्रिमूर्ति महंगाई के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

श्री नितिन गडकरी ने तेंदुलकर कमेटी का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश से गरीबी खत्म होने के बदले गरीबों की संख्या में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगाई से किसानों को लाभ हो रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि महंगाई से किसानों को तो कोई लाभ नहीं हुआ। अलबत्ता सरकार ने विदेशों में सुअर को खिलाने वाला लाल गेहूं 19 रुपए प्रति किलो की दर से आयात किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी मिलीभगत की वजह से महंगाई मामले में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। श्री गडकरी ने कहा कि 99 फीसदी कमोडिटी एक्सचेंज किया गया है, जिसकी वजह से दो लाख 80 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। आम जनता को कारपोरेट्स, मैनीपुलेटर्स, बड़ी कंपनियां और बिचौलिए लूट रहे हैं।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि 1998 में प्याज के दामों की कीमत तत्कालीन भाजपा सरकार को चुकानी पड़ी थी। मैं तब मुख्यमंत्री थी। मुझे जहां भी प्याज दिखता है मेरे आंसू निकल आते हैं। अब तो हर चीज़ ही मंहगी है और जनता को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

इस कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा एवं बड़ी संख्या में प्रदेश के नेताओं ने भाग लिया। ■

विधिवत रूप से नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गडकरी निर्वाचित

gekj: fo'k"k laoknnkrk }kjk

9 फरवरी 2010: भारतीय जनता पार्टी का अशोक रोड स्थित मुख्यालय– प्रातःकाल से ही हर्षोल्लास और धूमधाम का भव्य दृश्य। कारण– आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का विधिवत रूप नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाना था। पूरा केन्द्रीय कार्यालय उनके निर्वाचन की घोषणा की प्रतीक्षा में गाजेबाजे और पटाखों की गूंज से प्रतिध्वनित हो रहा था।

आज भाजपा के राष्ट्रीय निर्वाचन प्रभारी श्री थावरचन्द गहलोत ने भाजपा के नए अध्यक्ष श्री घोषणा करनी थी, इसलिए भाजपा के वरिष्ठ तथा अन्य नेताओं के साथ पूरा मुख्यालय कार्यकर्ताओं के समूह से भरा पड़ा था।

राजधानी में पिछली रात्रि से बूंदाबांदी का दृश्य छाया हुआ था, फिर भी भाजपा का मुख्यालय पूरी उमंग से परिपूर्ण था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे शुरू हुई जब राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री गहलोत ने नामांकन पत्र प्राप्त करना शुरू किया। उन्हें 12 बजे के निर्धारित समय तक कुल 19 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 18 नामांकन पत्र राज्यों से प्राप्त हुए और एक नामांकन पत्र भाजपा संसदीय दल से मिला। इन सभी में एक ही व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव था और वह थे– श्री नितिन गडकरी। श्री गहलोत ने इन सभी नामांकन पत्रों की जांच की और ये सभी ठीक पाए गए। नामांकन पत्र वापस लेने का समय एक बजे निर्धारित था और तब तक कोई भी नामांकन पत्र वापस नहीं लिया गया और इस प्रकार श्री नितिन गडकरी ही एक मात्र प्रस्तावित थे और निर्वाचन अधिकारी श्री थावरचंद गहलोत ने उन्हें निर्विरोध भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। श्री गहलोत ने श्री गडकरी को अपना निर्वाचन–पत्र प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया और श्री गडकरी ने इसे प्राप्त किया।

श्री गडकरी के निर्वाचन की घोषणा का स्वागत और अभिनन्दन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ जिसमें अपार समूह के साथ सभागार में अनेक वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, उनमें भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह और श्री एम. वेंकैया नायडू एवं श्री बंगारू लक्ष्मण, उपाध्यक्ष, श्री बाळ आपटे, श्री शांता कुमार, श्रीमती करूणा शुक्ला, महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय सहसंगठन सचिव श्री सौदान सिंह, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता श्री गोपीनाथ मुण्डे, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता श्री एसएस अहलूवालिया, महासचिव श्री अनंत कुमार और श्री विजय गोयल, राष्ट्रीय सचिव श्री प्रभात झा, श्री बलबीर पुंज और सुश्री सरोज पाण्डे, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष श्री शाहनवाज हुसैन, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अमित ठाकर, अनु. जाति मोर्चा अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जटिया, भाजपा मुख्यालय प्रभारी श्री श्याम जाजू, श्री किरीट सोमैय्या, श्री चंदन मित्रा, मीडिया सेल सह–प्रभारी श्री संजय मयूख, अनेक राज्यों के भाजपा अध्यक्ष, भाजपा सांसद, विधायक, मेयर, पूर्व–सांसद तथा पूर्व–विधायक, पूर्व अध्यक्ष एवं महासचिव शामिल थे।

इससे पूर्व पार्टी मुख्यालय आगमन पर श्री गडकरी का पारम्परिक ढंग से स्वागत करते हुए तमिलनाडु, उत्तराखंड और पंजाब के सांस्कृतिक कलाकारों ने बड़े धूमधाम के साथ नगाडे तथा अन्य वाद्य संगीत से पूरे वातावरण में उत्साह भर दिया। इस अवसर पर पटाखों की गड़गडाहट ने पूरे माहौल को गुंजायमान कर दिया। जब गडकरी जी हाल में प्रवेश करने लगे तो गगन ने भी हल्की बूंदे टपका कर उनके स्वागत में शुभ शकुन का परिचय दिया।

चुनाव की घोषणा के बाद श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री एम. वेंकैया नायडू, श्री राजनाथ सिंह और श्री थावरचंद गहलोत ने श्री नितिन गडकरी को मंच पर लेकर गए।

अपने उद्बोधन में श्री गडकरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित करने पर अपना आभार प्रगट किया। उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर

गौरव महसूस कर रहा हूं जिसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जैसी महान विभूतियों ने सुशोभित किया था।

उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान, उत्तरदायित्व और चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे मैं अपनी भरपूर क्षमता और अपने वरिष्ठ नेताओं के समर्थन, सहायता और मार्गदर्शन से पूरा करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पार्टी में अपने कई नेताओं से करिष्ठ हूं और मैं विनम्रतापूर्वक अपने सभी वरिष्ठजनों का आदर करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे सभी निर्णय अपने सभी सहयोगियों के परामर्श और मार्गदर्शन से सामूहिक रूप से लिए जाएंगे।

उन्होंने इस बात पर गर्व किया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जिसमें मेरे जैसा साधारण सा कार्यकर्ता, जिसने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत दीवारो पर पोस्टर चिपका कर और लिखने से की, वह आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। मैं न तो किसी प्रधानमंत्री का पुत्र था और न ही किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाती होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर भी आज मुझे अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है, यह गौरव की बात है और यही सिद्ध करता है कि भाजपा की पहचान अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग है।

पिछले पांच सप्ताहों में, मैं इस पद पर रहते हुए मैंने सभी की सहमति से पार्टी में आम सहमति बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कोई समस्या आती थी तो मैं श्री आडवाणी, श्री अरूण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उस पर चर्चा करता था।

श्री गडकरी ने कहा कि हमें पार्टी को और उच्च शिखर तक ले जाना है और यह आप सभी की सहायता और समर्थन से ही संभव हो पाएगा।

श्री गडकरी ने राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में पार्टी संविधान के प्रत्येक शब्द और भावना का अनुसरण करते हुए इन्हें सम्पन्न कराया।

जब श्री गडकरी सभागार से बाहर निकले तो बादल छंट गए थे और सूर्य अपनी आभा लेकर प्रगट हो गया था, जैसे संदेश दे रहा हो कि उनके नेतृत्व में पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है।

समारोह सम्पन्न होने के बाद श्री गडकरी को इस अवसर पर विशेष रूप से निर्मित मंच पर ले जाया गया जहां नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्षों तथा प्रदेशों के अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्पमाला पहना कर अपनी शुभकामनाएं देते हुए अभिनन्दन किया।■

नैतिक मूल्यों पर कुठाराघात बंद हो : महिला मोर्चा

श्री यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद की पुस्तक द्रोपदी'' कादम्बरी में द्रोपदी व श्री कृष्ण के विषय में अश्लील भाषा के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की।

भा.ज.पा सांसद व राष्ट्रीय महिला मोर्चा प्रभारी, श्रीमती सुमित्रा महाजन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज दिनांक 4 फरवरी, 2010 को महामहिम राष्ट्रपति माननीया प्रतिभा पाटिल से मिला। सुमित्रा जी ने राष्ट्रपति महोदया से कहा कि श्री यरलगड्डा लक्ष्मीप्रसाद की रचना ''द्रोपदी'' नामक कादम्बरी के संदर्भ में एक प्रतिनिधि मण्डल के साथ मुलाकात करने गई। पुस्तक में द्रोपदी के बारे में अश्लील बातें लिखी गई है और उसे वासना की प्रतिमूर्ति बताया गया है तथा भगवान श्री कृष्ण का द्रोपदी के प्रति भाव गलत ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक का आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी ने सन् 2010 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार घोषित किया है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने महामहिम माननीया श्रीमती प्रतिभा पाटिल को बताया कि यह पुस्तक हमारी पौराणिक, ऐतिहासिक ग्रन्थों पर आघात है। इसलिए ऐसे लेखक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार देना नैतिक मूल्यों पर कुठाराघात है। महामहिम ने माना कि हमारे पौराणिक व्यक्तित्वों पर टिप्पणी करना भारतीय संस्कृति पर चोट है। साथ ही उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर जवाब मांगने व व्यक्तिगत जांच कराने का आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधिमण्डल में भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती लतिका शर्मा, कार्यालय मंत्री, श्रीमती सिम्मी जैन, दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, श्रीमती उषा बडोला आदि महिलाएं उपस्थित थी। ■

यूपीए सरकार की गलत नीतियों के कारण बेलगाम हुई महंगाई : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई पर केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उससे ''आम आदमी'' बेहाल हुआ है। उनके भाषण के प्रमुख अंश नीचे प्रस्तुत हैं:

dkग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की भारी विफलता के कारण 'खाद्य पदार्थों' की महंगाई बढ़ी है। यह विडम्बना ही है कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही सरकार ने 'आम आदमी' को बदहाल कर दिया है और उसे अपनी दाल–रोटी जुटाना भी मुहाल हो गया है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है और सरकार की दूरदृष्टि और कार्यों की गहरी विफलता है। कृषि, वाणिज्य, खाद्य और उपभोक्ता कार्य एवं वित्त मंत्रालय– सभी इसके लिए जिम्मेदार है।

सरकार को विस्तार से इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि किस प्रकार से वस्तु–विनिमय की हेराफेरी के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। आवश्यक वस्तुओं के अगाऊ सौदों के पिछले वर्ष के रिकार्ड से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका कारण 99 प्रतिशत सट्टेबाजी और 1 प्रतिशत सुपुर्दगी रही है। इन विनियमों में भारी हेराफेरी हुई है। भाजपा मांग करती है कि आवश्यक खाद्य–कृषि पदार्थों को अगाऊ व्यापार सूची से स्थायी रूप से अलग किया जाए। श्री गडकरी ने कहा–

सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण गेहूं, चावल, चीनी, दालों की कीमतें पिछले कुछ महीनों में दुगुनी हो गई हैं।

सामान्य मुद्रास्फीति तथा खाद्य–पदार्थों की महंगाई के बीच भारी अंतर दिखाई पड़ता है। पिछले छह महीनों में सामान्य मुद्रास्फीति 1 से 8 प्रतिशत बढ़ी, परन्तु खाद्य वस्तुओं का मूल्य–सूचकांक 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ गया।

सरकार बफर स्टाक का इस्तेमाल भी सही ढंग से नहीं कर पाई है। उपभोक्ताओं को किसानों को दिए गए मूल्य से तिगुनी कीमत चुकानी पड़ती है।

आवश्यक वस्तुओं के अगाऊ व्यापार में 99 प्रतिशत सट्टेबाजी होती है जबकि वास्तव में 1 प्रतिशत की सुपुर्दगी हो पाती है। इन सभी नीतियों का लाभ मल्टीनेशनल और कार्पोरेट कम्पनियों, धोखेबाजों, सट्टेबाजों और कालाबाजारियों को मिलता है।

2009 की पिछली तिमाही में कमोडिटीज कम्पनियों का लाभ बढ़ कर 500 से 2900 प्रतिशत हो गया।

2009 में चावल का 991 लाख टन रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद, 2004 में 10 रूपए/ प्रति किलोग्राम का मूल्य बढ़कर 2010 में 32 रूपए/प्रति किलोग्राम हो गया। किसानों को केवल 9.50 रूपए/प्रतिकिलोग्राम मिलता है तो उधर उपभोक्ताओं को 32 रूपए/प्रतिकिलोग्राम मूल्य चुकाना पड़ता है।

गेहूं का उत्पादन 2006/07 में 758 लाख टन था, जो बढ़कर 2008–09 में 805 लाख टन हो गया। किसानों को 10 रूपए/प्रतिकिलोग्राम मिलता है तो उपभोक्ता चुकाता है– 24 रूपए प्रतिकिलोग्राम। 2009 में फिर से अगाऊ व्यापार की शुरूआत हुई।

कमोडिटी एक्सचेंज में 14 लाख टन की टर्नओवर में से वास्तविक सुपुर्दगी 1400 टन होती है– इस प्रकार मई से दिसम्बर 2009 के दौरान 99.99 प्रतिशत सट्टेबाजी का व्यापार हुआ।

चीनी

आयात–निर्यात की हेराफेरी

- 2008–09 में 12.50 रूपए/प्रतिकिलोग्राम के हिसाब से 48 लाख टन का निर्यात हुआ।
- अब कच्ची चीनी का आयात 36 रूपए/प्रतिकिलोग्राम से हो रहा है।

सरकार निर्यातकों को निर्यात और परिवहन सब्सिडी देती है। सरकार ने चीनी का बफर स्टाक क्यों नही बनाया?

एक वर्ष में 22 रूपए से 45–50 रूपए प्रतिकिलोग्राम तक पहुंच गई।

कमोडिटी एक्सचेंज में सट्टेबाजी और हेराफेरी

2009 का टर्नओवर 79 लाख टन परन्तु सुपुर्दगी 1.11 लाख टन, सट्टेबाजी

98.6 प्रतिशत।

मई 2009 से अगाऊ व्यापार पर प्रतिबंध लगा। दालों की कीमतें बढ़कर 200 से 400 प्रतिशत तक पहुंची। 2004 में एनडीए/ बीजेपी सरकार में चना दाल 25 रूपए/प्रति किलोग्राम मिलती थी जो अब जनवरी 2010 में 56 रूपए/प्रति किलोग्राम मिलती है। तब तुर दाल का भाव 24 रूपए/प्रति किलोग्राम था। तुर दाल ने शतक लगाया तो चीनी ने अर्धशतक।

खाद्य तेल

मूंगफली तेल का भाव बढ़कर जा पहुंचा 40 रूपए से 100 रूपए प्रति किलोग्राम। 2008–09 में भारत ने 75 लाख खाद्य तेल का आयात किया अर्थात् अपनी खपत का 50 प्रतिशत से अधिक। भारतीय खाद्य सुरक्षा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कमोडिटी एक्सचेंज व्यापारियों के हाथ गिरवी रखी जा रही है।

कमोडिटी एक्सजेंज में हेराफेरी और सट्टेबाजी भयानक स्तर पर हो रही है।

चना

टर्नओवर 2,59,43,840 टन– सुपुर्दगी 50,710 टन सट्टेबाजी 99.80 प्रतिशत।

जीरा

टर्न ओवर 21,82,923 टन, सुपुर्दगी 3402 टन सट्टेबाजी 99.84 प्रतिशत

कीमतें 104 रूपए से बढ़कर 2009 में 146 रूपए प्रतिकिलोग्राम हो गई।

गुवार बीज

टर्न ओवर 9,02,97,720 टन, सुपुर्दगी 21,550 टन सुपुर्दगी 0.02 प्रतिशत और सट्टेबाजी 99.98 प्रतिशत।

हल्दी

कमोडिटी एक्सचेंज हेराफेरी का ज्वलंत उदाहरण हल्दी है।

उत्पादन 1,32,72,060 टन

सुपुर्दगी 3,880 टन

सट्टेबाजी 99.97 प्रतिशत

कीमतें 30 रूपए से बढ़कर 130 रूपए/प्रतिकिलोग्राम हुई।

आलू

आलू को अगाऊ व्यापार में शामिल करने से पता चलता है कि भारत में कमोडिटी एक्सचेंज का कितना अधिक दुरूपयोग होता है।

टर्नओवर 32,53,020 टन, वास्तविक सुपुर्दगी 4,080 टन, सट्टेबाजी 99.70 प्रतिशत और सुपुर्दगी 0.30 प्रतिशत। 6 रूपए से बढ़कर कीमतें 14 रूपए/प्रतिकिलोग्राम हुईं।

सरकार महंगाई नियंत्रित करने को लेकर गंभीर नहीं : भाजपा

नई दिल्ली में एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल ने सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्दि हुई है और आम आदमी भर पेट भोजन से भी वंचित हो गया है। 23 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 17.56 प्रतिशत को छू गई है। दिल्ली की रिटेल मार्केट में एक वर्ष में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तुर दाल 49 रूपए से 83 रूपए किलो, उड़द 46 रूपए से 71 रूपए किलो, मूंग 46 रूपए से 82 रूपए किलो, चीनी 24 रूपए से 50 रूपए किलो, गेहूँ 13 रूपए से 16 रूपए किलो, आटा 15 रूपए किलो से 18 रूपए किलो, खुली चाय 143 रूपए किलो से 160 रूपए किलो हो गई है। दूध के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हो गई है। आलू की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

उक्त भाजपा नेताओं ने आशंका व्यक्त की कि यदि पारिख कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर सरकार पैट्रों उत्पादों की कीमतों में भारी इजाफा कर देती है तो मंहगाई पूरी तरह बेकाबू हो जाएगी। स्मरण रहे कि पारिख कमेटी ने तेल कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की है। पारिख कमेटी ने एलपीजी के सिलेंडर में 100 रूपए की वृद्धि, केरोसिन में 6 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि, पैट्रोल में 4 रूपए 72 पैसे की वृद्धि और डीजल में 2 रूपए 33 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की सिफारिश की है।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मंहगाई को नियंत्रित करने के मामले में गम्भीर नहीं है। ठोस और कारगर कदम उठाने की बजाए वह आए दिन तर्क और बहाने पेश कर रही है। वह कभी उत्पादन में कमी को, कभी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ी कीमतों को, कभी राज्य सरकारों की लापरवाही को और कभी लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि को मंहगाई का कारण बताकर पल्ला झाड़ रही है। एक ओर कृषि उत्पादों के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है और दूसरी ओर वर्ष 2006–07 के मुकाबले वर्ष 2008–09 में कृषि उत्पाद के निर्यात में भारी बढ़ोतरी की गई है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि पारिख समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की गई तो वर्तमान वित्त वर्ष के अन्त तक मार्च में मुद्रास्फीति 9 से 10 प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ जाएगी जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें और चढ़ जायेंगी।■

भाजपा मांग करती है कि-

कमोडिटी एक्सचेंज अगाऊ व्यापार सूची से खाद्य पदार्थों हो हटाया जाए।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और बफर स्टाक बनाया जाए।

किसानों के साथ ठगी तथा आम आदमी को लूटने की आर्थिक नीति बंद की जाए।

सार्वजनिक प्रणाली व्यवस्था (पीडीएल) से लेकर बीपीएल श्रेणी तक के माध्यम से सब्सिडाइज्ड कीमतें देकर गेहूं, चावल, चीनी, दालों की कीमतों को कम किया जाए।

जमाखोरों, काला बाजारियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों/कार्पोरेट कम्पनियों की हेराफेरी। लाभ कमाने की आदत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इन सब पर मानीटरिंग हो। ■

पेशकश के पीछे का सच

ykyÑ".k vkMok.kh

वर्ष 2008 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के दौरान बराक ओबामा ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए वे कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए गंभीरता से प्रयास करेंगे। अगर वे चुनाव जीते तो उनके प्रशासन के लिए यह महत्वपूर्ण कामों में से एक होगा। 'टाइम' पत्रिका के संवाददाता 'जो क्लेन' के साथ विस्तार से बातचीत करते हुए बराक ओबामा ने कहा था, ''कश्मीर में इन दिनों जैसी दिलचस्प स्थिति है उसमें इस मसले को कब्र से निकालकर हल करने की एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। हमें इस मसले के हल के लिए गंभीरता से प्रयास करना होगा। इसके लिए एक विशेष दूत नियुक्त करना, आंकड़ेबाजी के बजाय सही मायने में प्रयास और खास तौर पर भारतीयों को यह समझाना और इसके लिए तैयार करना होगा कि आज जब आप एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं तब इस मसले को हल कर इससे क्यों नहीं मुक्त हो जाते? इसी तरह पाकिस्तानियों को यह समझाना होगा कि भारत आज कहां है और आप कहां हैं। आपके लिए कश्मीर मसले पर फंसे रहने से ज्यादा जरूरी है अफगान सीमा की बड़ी चुनौतियों से जूझना। मैं जानता हूं कि यह सब करना और इसमें कामयाब होना इतना आसान नहीं होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि यह हो जाएगा।''

पिछले हफ्ते अचानक भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए प्रस्ताव दिया, उसने स्वाभाविक रूप से कई राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया। आज देश यह जानने को इच्छुक है कि जिस तरह अचानक पाकिस्तान को बातचीत का न्योता दिया गया, क्या उसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का दबाव है? लोग यह साफ–साफ जानना चाहते हैं कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत ने दृढ़तापूर्वक जो ऐलान किया था उसका क्या हुआ? याद कीजिए, तब भारत ने कहा था कि जब तक मुंबई हमले की योजना बनाने वाले साजिशकर्ताओं के खिलाफ पाकिस्तान ठोस कार्रवाई नहीं करता और अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त नहीं करता तब तक उसके साथ किसी तरह की कोई वार्ता नहीं हो सकती, लेकिन विदेश सचिव स्तर की वार्ता के मसले पर सरकार का यह हालिया यू–टर्न क्या वाशिंगटन के जोरदार दबाव का नतीजा है? गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से ही भारत उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए बातचीत की मेज पर आने को राजी हुआ। 22 फरवरी, 1994 को जम्मू और कश्मीर को लेकर लोकसभा में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसे आखिरकार संप्रग सरकार कैसे नजरअंदाज कर सकती है! आज वार्ता के लिए पाकिस्तान जिस अकड़ और कुटिलता से भारत की ओर देख रहा है उसके बाद तो संप्रग सरकार के कथित सख्त रवैये की चर्चा करना ही शायद बेमानी है। इसके बाद यह याद करना और भी जरूरी है कि लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर मसले पर किस तरह साफ शब्दों में अपना मंतव्य रखा था, जिसे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। उस प्रस्ताव में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं उस पर यहां दोबारा सोचना–विचारना अनुचित न होगा।

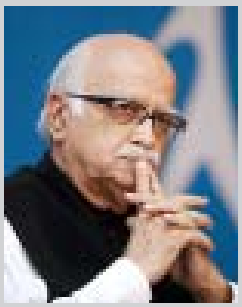

पिछले हफ्ते अचानक भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह विदेश सचिव स्तर की वार्ता के लिए प्रस्ताव दिया, उसने स्वाभाविक रूप से कई राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया। आज देश यह जानने को इच्छुक है कि जिस तरह अचानक पाकिस्तान को बातचीत का न्योता दिया गया, क्या उसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का दबाव है? लोग यह साफ–साफ जानना चाहते हैं कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत ने दृढ़तापूर्वक जो ऐलान किया था उसका क्या हुआ?

''पाकिस्तान जिस तरह अपने कब्जे वाले कश्मीर सहित अपनी सरजमीं के अन्य हिस्सों से आतंकियों को हथियार, धन और गोलाबारुद देकर जम्मू–कश्मीर में तबाही के लिए भेजता है वह इस सदन के संज्ञान में है। पाकिस्तान हथियार, धन और अपने यहां प्रशिक्षण देकर भाड़े के विदेशी लड़ाकों को जम्मू–कश्मीर में अव्यवस्था और अराजकता फैलाने के लिए भेजता है। पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हत्या, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और स्थानीय निवासियों को डरा–धमकाकर वहां दहशत भरा माहौल बनाना चाहते हैं। यह सदन जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों, वहां की जनता के शोषण, भयादोहन और वहां के मासूम नागरिकों के साथ जो जघन्य अपराध कर रहे हैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह सदन मांग करता है कि पाकिस्तान तत्काल आतंकवादियों का समर्थन करना बंद करे, जो सरासर शिमला समझौते का उल्लंघन है।

याद रहे कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के तनाव या किसी मसले पर बातचीत के लिए शिमला समझौते को

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया था। सदन ने इस बात को भी दोहराया था कि भारत का राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढांचा और हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है।

जम्मू–कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों को लेकर पाकिस्तान की झूठे, बेबुनियाद और दुष्टतापूर्ण आरोपों को हम अस्वीकार करते हैं। पाकिस्तान की भारतविरोधी गतिविधियों और शरारतपूर्ण बयानबाजी निंदनीय है। इस सदन ने इस बात को भी नोट किया है कि पाकिस्तान की उत्तेजक बयानबाजी से राज्य के लोगों की राय दूषित होती है और माहौल में उत्तेजना फैलती है। जम्मू–कश्मीर के लोगों के जनमत को प्रभावित करने, स्थानीय माहौल में तनाव बढ़ाने और जनता को उकसाने के लिए पाकिस्तान लगातार उकसाऊ बयान देता रहता है। यह बेहद अफसोस की बात है कि जम्मू–कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है उस हिस्से में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का वहां हनन हो रहा है। हम भारत के नागरिकों की ओर से पुरजोर ताकत से यह ऐलान करते हैं कि..

- जम्मू–कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था, अविभाज्य अंग है और अविभाज्य अंग रहेगा। इसे देश के बाकी हिस्सों से बांटने और अलग करने के किसी भी तरह के प्रयास का सभी आवश्यक तरीकों से हम विरोध करेंगे।
- भारत ने अपनी एकता, अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए हर तरीके से मुकाबला किया है और इस पर आंच आने की स्थिति में भविष्य में भी पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। हम यह मांग करते हैं कि पाकिस्तान जम्मू–कश्मीर के जिस भूभाग को कथित रूप से आजाद कश्मीर कहता है उस पर आक्रमण करके उसने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
- पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर राज्य के जिन हिस्सों पर जबरन और अवैध रूप से आज तक कब्जा किया हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए।
- जम्मू–कश्मीर के बारे में किसी तरह की बयानबाजी और षडयंत्रकारी गतिविधियों को भारत अपने आंतरिक मामलों में बेजा दखल मानेगा और उसका पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा।

सरकार, देश और साथ ही दुनिया को इस प्रस्ताव को ध्यान रखना चाहिए।■

(लेखक भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष हैं)

लद्दाख जाकर चीनी अतिक्रमण की सच्चाई जानेगी भाजपा टीम

Hkkजपा ने चीन की आक्रामक नीति की ओर केंद्र का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट है कि चीन ने लद्दाख में भारत के कुछ भू–भाग पर कब्जा कर लिया है। भाजपा ने इसकी जांच के लिए अपना पांच सदस्यीय दल भेजने की भी घोषणा की।

यह दल मौके पर जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को सौंपेगा। भाजपा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नेपाल के साथ दिन प्रतिदिन अनावश्यक रूप से उलझ रहे मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल जाने का भी सुझाव दिया है। भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में शिवशंकर मेनन की नियुक्ति पर भी ऐतराज जताया और कहा कि यह माना जाता है कि चीन और पाकिस्तान के प्रति मेनन का रवैया अपेक्षाकृत नरम है।

भाजपा के मुताबिक, लद्दाख जाने वाले दल में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी, हिमाचल प्रदेश से सांसद राजन सुशांत, पूर्व सांसद तापिर गाओ और जम्मू–कश्मीर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल सिंह होंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने चिंता जताते हुए कहा कि चीन अपने हितों के आड़े आने वाले देशों पर आक्रमण करने की तंग–श्याओ–पिंग से पूर्व की अपनी नीति पर फिर से लौट आया है। पाकिस्तान के साथ बढ़ता उसका खतरनाक गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता है। चीन की इस हठधर्मिता और युद्ध प्रवृत्ति की ओर बढ़ते संकेत पूरी तरह से स्पष्ट होने के बावजूद भारत सरकार की ओर से जानबूझ कर उसे कमतर आंकने के प्रयास किए जा रहे हैं

श्री प्रसाद का कहना था कि चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं में गंभीर निहितार्थ छिपा है। भारत के निकट मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या मालदीव आदि देशों में चीन अपने भू–राजनीतिक हित बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। भाजपा चीन के साथ वार्ता के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत को अपने सामरिक हितों की चिंताओं को कम करके नहीं आंकना चाहिए। भारत सरकार को खतरे की पहचान कर निश्चित सीमा में सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की परियोजना चलानी चाहिए। भारत को यथोचित और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना चाहिए, और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ नई कूटनीतिक पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को नेपाल जाकर पड़ोसी देश के साथ उलझ रहे मुद्दों को सुलझाना चाहिए।

श्री प्रसाद का कहना था कि चीन और पाकिस्तान का बढ़ता गठबंधन गंभीर चिंता का विषय है। पाकिस्तान के सैनिक हार्डवेयर में चीन का 70 प्रतिशत अंशदान है। वह प्रौद्योगिकी नियंत्रण नियमों का उल्लंघन कर पाकिस्तान को क्रूज और बेलिस्टिक मिसाइलें उपलब्ध करा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर उसके आक्रामक तेवर और लद्दाख सहित अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा उल्लंघन उसके कुत्सित इरादों का खुलासा करते हैं।

उन्होंने चीन के इस आचरण के बारे में देश में सामरिक समुदाय और सैन्य विशेषज्ञों की राय में अंतर बताया। उनका कहना था कि पार्टी अध्यक्ष द्वारा गठित समिति लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर भारत में चीनी सेना के बढ़ते अतिक्रमण से पैदा होने वाली धमकी की वास्तविकता के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। ■

स्वायत्तता का सवाल

t xekgu

टस्टिस सगीर अहमद की अध्यक्षता में कश्मीर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट से एक बार फिर कश्मीर की स्वायत्तता का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। इस समूह के गठन की घोषणा 24 और 25 मई 2006 को श्रीनगर में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। सगीर अहमद आयोग की ओर से ढाई साल बाद जो रिपोर्ट पेश की गई वह आकार में जितनी मोटी है, मामले की पड़ताल में उतनी ही हल्की है। असलियत में सगीर अहमद की अध्यक्षता वाले समूह का कामकाज कुल मिलाकर बेकार की कवायद ही साबित हुई है। अतीत की घटनाओं के विस्तृत वर्णन के बाद, जो प्रबुद्ध तबके को पहले ही मालूम है, रिपोर्ट बस यह कहकर संतुष्ट हो जाती है कि स्वायत्तता की मांग की पड़ताल कश्मीर समझौता या किसी अन्य प्रकार या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री को स्वायत्तता को पुनर्स्थापित करने में जो उचित लगे उस आधार पर की जा सकती है। यह भारतीय संविधान के किसी भी संघीय कानून या प्रावधान को हटाने या अन्यथा कोई अन्य विशेष अनुशंसा नहीं करती। तथाकथित रूप से संविधान के राज्य तक विस्तार के कारण ही कश्मीर को स्वायत्तता गंवानी पड़ी है।

कश्मीर के मामले में जस्टिस सगीर अहमद की दुविधा समझ में आती है। अगर उन्होंने जम्मू–कश्मीर में संवैधानिक प्रावधानों के विस्तार की पड़ताल की होती तो उन्हें पता चलता कि समय–समय पर किए गए तमाम विस्तार न केवल कानूनी और संवैधानिक आधार पर, बल्कि संघ और राज्य के बीच मधुर कार्यकारी संबंध विकसित करने के लिए भी न्यायोचित थे। उन्हें यह भी पता चलता कि इनमें से किसी भी विस्तार ने किसी भी रूप में कश्मीर की पहचान या व्यक्तित्व, जिसे कश्मीरियत कहा जाता है, को नहीं घटाया है। इस प्रकार के निष्कर्ष निश्चित तौर पर जस्टिस सगीर अहमद को उन तत्वों का प्रिय नहीं बनाते जो अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थो को पूरा करने के लिए कश्मीरी जनता की संवैधानिक निरक्षरता का लंबे समय से फायदा उठा रहे हैं। इसलिए, उन्होंने कम से कम प्रतिरोध का रास्ता पकड़ा, जो असल मुद्दों से बचता हुआ निकल जाता है। साथ ही उन्होंने कोई ठोस सुझाव या अनुशंसा भी नहीं की है। उनकी रिपोर्ट से केंद्र या राज्य सरकार को व्यावहारिक नीति बनाने में शायद ही कोई दिशानिर्देश मिले। दुर्भाग्य से, कई सालों से निहित स्वार्थी तत्व कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। वे ठोस तथ्यों को छिपा रहे हैं और इस बात का कुप्रचार कर रहे हैं कि कश्मीर से स्वायत्तता का पूर्व में किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया है। ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं, किंतु ये आम कश्मीरी के मन में कुछ मुगालते भरने में कामयाब जरूर रहे हैं। यह सही समय है जब केंद्र सरकार को इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए और इस मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों को खूब प्रचारित करना चाहिए।

कई सालों से निहित स्वार्थी तत्व कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। वे ठोस तथ्यों को छिपा रहे हैं और इस बात का कुप्रचार कर रहे हैं कि कश्मीर से स्वायत्तता का पूर्व में किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया है। ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं, किंतु ये आम कश्मीरी के मन में कुछ मुगालते भरने में कामयाब जरूर रहे हैं। यह सही समय है जब केंद्र सरकार को इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए और इस मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों को खूब प्रचारित करना चाहिए।

असलियत यह है कि जम्मू–कश्मीर राज्य और केंद्र के बीच कार्यकारी व्यवस्था के तहत 1952 में जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने आपसी विचार–विमर्श के आधार पर एक समझौता किया था, जिसे दिल्ली समझौता नाम दिया गया। इस समझौते के आलोक में ही भारत के राष्ट्रपति ने संविधान आर्डर, 1954 जारी किया। इस आदेश में समय–समय पर संशोधन किए गए ताकि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान राज्य तक विस्तारित हो सकें। 1954 के राष्ट्रपति के आदेश से ही राज्य में वित्तीय एकीकरण प्रभावी हो पाया। तभी केंद्र सरकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डाकखानों और नागरिक उड्डयन पर नियंत्रण स्थापित हो पाया। कश्मीर के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिकार 1958 में मिला। 1960 में सुप्रीम कोर्ट को जम्मू–कश्मीर हाईकोर्ट के फैसलों पर विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई की शक्तियां मिलीं। चुनाव आयोजित करने में चुनाव आयोग को निरीक्षक की भूमिका की भी अनुमति दे दी गई, यद्यपि वहां चुनाव राज्य के कानून के अनुसार होते रहे। 1965 में अनुच्छेद 356 और 357 जम्मू–कश्मीर में प्रभावी हुआ। 1968 में केंद्रीय अनुसूची में 72वीं प्रविष्टि की गई, जिसके तहत चुनावी याचिकाओं पर हाई कोर्ट के फैसले की सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिल गया। इन विस्तारों और अनुप्रयोगों के संदर्भ में सदरे–रियासत और जम्मू–कश्मीर के प्रधानमंत्री का पदनाम, दर्जा, कार्य और नियुक्ति की प्रक्रिया बेमानी हो गई। इसलिए यहां जरूरी और उचित समझा गया कि सदरे–रियासत और प्रधानमंत्री का पदनाम और नियुक्ति का तरीका बदला जाए। इस संबंध में जरूरी संशोधन 1966 में राज्य की विधानसभा ने खुद ही जम्मू एवं कश्मीर संविधान में संशोधन करके किया।

आखिर इन सुधारों में क्या बुराई

है? किस तरह ये आम कश्मीरी के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं? ये तो राज्य की विधानसभा की सहमति से संवैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को सुचारू करते हैं। जो लोग इस आधार पर इन बदलावों को गलत ठहराते हैं कि परिदृश्य से शेख अब्दुल्ला की अनुपस्थिति से कश्मीरियों के हित प्रभावित हुए हैं, वे यह भूल जाते हैं कि इस संबंध में प्रासंगिक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारें हैं। संपत प्रकाश बनाम जम्मू–कश्मीर राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम परिवर्तनों की संवैधानिक वैधानिकता पर मुहर लगा दी। कश्मीर संधि पर हस्ताक्षर करते समय इंदिरा गांधी ने 24 फरवरी, 1995 को संसद में दिए गए बयान में कहा था– ''शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट कर दिया गया है कि घड़ी की सुईयां उल्टी नहीं घूमेंगी और केंद्र व राज्य के बीच के बंधनों में कोई कमजोरी नहीं आएगी।'' भारत सरकार केवल एक बिंदु पर विचार करने को सहमत हुई थी कि समवर्ती सूची में से किसी भी मामले पर अगर राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजती है तो भारत सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, किंतु न तो शेख अब्दुल्ला और न ही फारुक अब्दुल्ला की सरकार ने केंद्र सरकार के विचारार्थ ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा।

राज्यसभा में मेरे अतारांकित प्रश्न नंबर 1871 के जवाब में भारत सरकार ने 14 दिसंबर, 1995 को कहा– 1975 की अवधि तक राज्य सरकार ने विस्तारित किए गए किसी संवैधानिक प्रावधान या कानून को वापस लेने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।'' कश्मीर संधि में पुनर्विचार के स्पष्ट प्रावधान के बावजूद फरवरी 1953 से 1975 तक किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव न भेजने का यह कारण था कि ये प्रावधान व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए जरूरी थे और राज्य के आम आदमी के हितों से जुड़े थे। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग के कार्याधिकार में विस्तार या सुप्रीम कोर्ट अथवा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधिकारों का दायरा बढ़ाने पर कोई आपत्ति कैसे दर्ज कराई जा सकती है? ये विस्तार तो सिर्फ इसलिए किए गए ताकि जम्मू–कश्मीर में न्यायिक तंत्र का बेहतर ढांचा स्थापित किया जा सके अथवा लेखा परीक्षण से संबंधित बेहतर प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा सके या फिर चुनाव आयोजित करने के लिए एक अधिक स्वतंत्र इकाई इस राज्य में स्थापित की जा सके। ■

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

कांग्रेस दिखावा न कर समाज विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटे: राजनाथ सिंह

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा 2 फरवरी को जारी प्रेस वक्तव्य

dkंग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से एमएनएस तथा अन्य ऐसे ही उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया दी है वह लोगों का ध्यान दूसरी दिशा में खींचने का प्रयास मात्र है और वह ऐसा कर के किसी भी प्रकार का ठोस उपाय करने की अक्षमता दिखा रही है तथा कांग्रेस वास्तविक मुद्दों को सुलझाने की बजाए उनके साथ धींगामुश्ती कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी सचमुच मानती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले नागरिकों ने मुम्बई और दिल्ली जैसे शहरों में बस कर इन नगरों की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है और मानती है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए तो उसे इन शहरों में बड़ी संख्या में रह रहे इन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए।

महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में है और उसके पास मराठी गरिमा के नाम पर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ नफरत फैलाने और हिंसा का उत्पात करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी शक्तियां प्राप्त है। कांग्रेस ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाए निष्क्रियता का परिचय दे रही है और अपनी रणनीति के रूप में इन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर रही है।

कांग्रेस पार्टी का तो देश में अलगाववादियों तथा क्षेत्रीय अभियान चलाने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान करने का एक लम्बा इतिहास मिलता है जिससे न केवल भारत का सेक्युलर ढांचा ध्वस्त हुआ है बल्कि देश की एकता और अखण्डता को भारी धक्का पहुंचा है। पंजाब में खालिस्तान अभियान, जम्मू और काश्मीर एवं पूर्वोत्तर के अनेक भागों में इस समय फैली भारत विरोधी भावना को लीजिए तो इन अभियानों के पीछे जुड़े लोगों में सक्रिय अथवा परोक्ष रूप में कांग्रेस का हाथ ही दिखाई पड़ेगा।

कांग्रेस की इस प्रकार की रणनीति ने कई बार स्वयं उसे ही धराशाई भी किया है परन्तु उसके ऐसे कृत्यों का प्रभाव लम्बे समय तक बना रहता है और इससे समाज–विरोधी और भारत–विरोधी तत्वों को संरक्षण मिलता रहता है। यदि कांग्रेस सचमुच लोगों का विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों का संरक्षण प्रदान करने के मामले में गम्भीर और ईमानदार है तो उसे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अपने राजनीतिक एजेण्डे की परिणति के लिए कानून हाथ में ले लेते हैं। ■

'राजनीति' से दूर मत भागिए

&çHkkr >k

jk जनीति' को कभी किसी ने उत्कृष्ट स्थान नहीं माना। पर जितने प्रखर राष्ट्रवादी हुए उनका नाम राजनीतिक क्षेत्र से ही हुआ। अतः यह कहने में कोई संकोच नहीं कि राजनीति का निकृष्ट स्थान, उत्कृष्ट कार्य करने का एक सहज स्थान है। बस! आपको तय करना है कि आप काम कैसा करना चाहते हैं?

'राजनीति' के प्रभाव बिना कौन सा कार्य हो रहा है? जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक राजनीतिक प्रभाव को समाज–यात्रा में सहज देखा जा सकता है। अतः जब कोई यह कहता है कि राजनीति से देश सुधर नहीं सकता तो हम उससे सहमत नहीं होते। हां! यह सत्य है कि सब कुछ राजनीति से नहीं हो सकता पर यह तो पूर्ण सत्य है कि बहुत कुछ राजनीति से हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा।

यह तो समाज को तय करना होता है कि वह कैसी राजनीति चाहती है। 'राजनीति' से आप दूर रहकर राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति में डूबकर भी आप राजनीति नहीं कर सकते। फिर क्या और कैसे? तो आपको पहले यह समझना होगा कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? यह सवाल सौ टके का है। देश में अधिकांश लोग जो राजनीति में हैं, वे राजनीति क्यों कर रहे हैं, वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं, इसकी स्पष्टता नहीं रखेंगे तो राजनीति सदैव आपको भटकायेगी। राजनीति रूतबा गालिब करने का स्थान नहीं है। न ही 'राजनीति' ग्लैमर की चीज है। 'राजनीति' न केवल पद है और न केवल प्रतिष्ठा। 'राजनीति' केवल तिकड़म भी नहीं है। लोग इसे धूर्तता और चार्तुयता का स्थान भी कहते हैं। 'राजनीति' न शौक है और न शगल। 'राजनीति' न स्वयं की गरीबी दूर करने का जरिया है और न ही जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद को पनपाने और राष्ट्रीयता को डूबोने का स्थान है। राजनीति न डराने का, न हंसाने का और न ही रूलाने का नाम है। राजनीति न केवल चुनाव है और न केवल विधायक, सांसद बनने का जरिया है। राजनीति न वंशवाद की विषबेल लगाने का केन्द्र है और न धंधा करने की मंडी। यहां न बोली लगनी चाहिए और न आचरण भ्रष्ट होना चाहिए। राजनीति न तो किसी को उजाड़ने का जरिया है और न स्वयं को सजाने और संवारने का। राजनीति न केवल अखबार की बयानबाजी है और न केवल चैनलों पर देने वाली बाइट है। राजनीति न परिक्रमा है और न मुंगेरीलाल के सपने। राजनीति न केवल बहस है

आज राजनीति समझने वालों लोगों की आवश्यकता है न कि राजनीति करने वालों की। अधिकता आज उनकी हो गई है जिनकी राजनीतिक समझ नहीं है वे राजनीति करने लगे हैं। फिर जब राजनीति नासमझों के हाथों में चली जाएगी तो फिर आप उनसे समझदारी की राजनीति की अपेक्षा क्यों करते हैं? जैसा बोया है, वैसा ही काटना पड़ेगा।

और न केवल सेमिनार। राजनीति न केवल स्वयं का भविष्य है और न अपराध पनपाने का केन्द्र। साथ ही न अपराधियों को संरक्षण देने का अड्डा है और न पुलिस और अदालतों को प्रभावित करने की एजेंसी। राजनीति न तो टेंडर भरने का जरिया है न निवेश करने का बाजार। राजनीति न सुरा–सुन्दरी में डूबे रहने का स्थान है और न अय्यासी का अखाड़ा है। राजनीति व्यापार, बाजार और व्यभिचार का नाम नहीं है। राजनीति न चक्का जाम और प्रदर्शन का नाम है और न ही राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ने का नाम है।

आखिर 'राजनीति' फिर है क्या? मुश्किल यही है कि जो राजनीति की समझ रखते हैं, वे राजनीति में प्रभावी नहीं हैं और जो राजनीति की समझ नहीं रखते हैं वे पूरी तरह हावी होने की कोशिश करते हैं। अच्छा यही होता कि जब कोई राजनीति में आए तो जनता के सामने अपनी बात साफ–साफ रख दे कि वह राजनीति में क्यों आया है? उसे अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। वह जिस कार्य के लिए आया है, यदि वह स्पष्ट बता देता है तो कम से कम जनता यह तो कहेगी, चलो बेचारे ने साफ–साफ बोल तो दिया। पर ऐसा नहीं होता। आते सभी है राष्ट्र सेवा के लिए। गरीबों के आंसू पोंछने के लिए। दूसरों की चिंता करने के लिए। पर क्या ऐसा वाकई होता है?

मुझे लगता है कि जो राजनीति में आता है, उसके सामने नेतृत्व का जैसा आदर्श होता है वह उसी मार्ग पर चल

देता है। अब आप कहेंगे कि राजनीति में मार्ग कौन हो सकता है? दिक्कत यही है लोग मार्ग तय नहीं करते और चलते रहते हैं। होता फिर यह है कि वे चलते–चलते वहां पहुंच जाते हैं, जहां–जहां से उन्हें पथ्य परहेज रखना होता है। वे फिर पहुंचते नहीं हैं, वे गिरने लगते हैं, रिसने लगते हैं।

धीरे–धीरे 'वे' राजनीति में क्यों आए, समझ जाते हैं। फिर क्या उसके बाद तो फिर वे राजनीति की इसी विधा को समझने लगते हैं। लग गई लाटरी। सफल हुआ जीवन। अपना ही नहीं सात पुश्तों का। धीरे–धीरे से परम्परागत धनाढ्य की श्रेणी में अचानक बने धनाढ्य भी शामिल हो जाते हैं, राजनीति की ओर एक टक निगाहों से सभी देखने लगते है। आओ–आओ सब दूख दूर करेंगे राम। इसके बाद लगती है होड़। लगे भी क्यों नहीं? कल तक जो मारे–मारे मांगते–मांगते फिर रहा था, आज लोग उसके पीछे! चमत्कार कैसे हुआ? लोग देखते हैं और वे भी उसी राजनीतिक दुनिया की तलाश करने लगते हैं, जो उसे रातों–रात पैसे वाला बना दे। राजनीति, गरीबी दूर करते–करते के नारों के साथ ही अमीर बनने का सस्ता जरिया बन गई।

सोचना चाहिए, कि हम देश किसके भरोसे सौंप रहे हैं। ये आधुनिक गांधीजी है। सरकार के धन से अपनी गरीबी दूर करते है और उसके लिए उन्हें एक भ्रष्ट तंत्र भी उपलब्ध रहता है, जो सदैव अनुचित मार्ग के सभी मार्ग बनाए रखता है। धीरे–धीरे राजनीति ऐसे ही लोगों के लिए वरदायिनी हो गई।

आप लाख कोसते रहें, उनका क्या होना है। वे तो फिर जीत जायेंगे, क्योंकि वे जनतंत्र की मंडी में वोटरों के थोक विक्रेताओं पर पैनी निगाह रखते हैं और उन वोट के थोक व्यापारियों की जेब सदैव गरम रहती है। समाज का यह तबका, जहां मिली चाय, वहीं बदली राय, की बढ़ती जनसंख्या से देश त्रस्त होता जा रहा है। 63वां स्वतंत्रता और 61वां गणतंत्र दिवस बीत जाने के बाद भी हम दो बूंद पानी, पेटभर रोटी, सिर छुपाने के लिए घर, तन ढकने के कपड़ों के लिए मोहताज हैं; आखिर यह कैसी राजनीति है?

राजनीति में सिर्फ एक बात रह गई है 'वोट कैसे मिले'। जैसे भी हो, वैसे मिले। एक बार मिल जाए फिर तो उसे जाने नहीं दूंगा।

हमें लगता है कि अब वह दिन नहीं लौटेगा, जब राजनीति समाज के लिए की जाती थी। राजनीति पर–पीड़ा दूर करने का माध्यम था। राजनीति नवनिर्माण के लिए होती थी। नैतिकता और प्रामाणिकता राजनीति की प्राणदायिनी थी। संवेदनशीलता, राजनीति की मांग की सिंदूर थी। 'नैतिकता' से जुड़ी राजनीति की समाज कद्र करता था। सहजता, सरलता, विनम्रता, राजनीति में मायने नहीं बल्कि मर्यादा बढ़ाती थी। पहले राजनीति में कार्यकर्ता बनाए जाते थे, अब समर्थक बनाए जाते हैं, वह भी दल का नहीं स्वयं का। यही कारण है कि राजनीति दल की नहीं जेब की हो गई। जिसकी जेब जितनी भारी, उसकी ओर जनता सारी। जनता भी क्या करे? उसकी भी आदत अब वैसी नहीं रही, जैसे पहले थी। अब राजनीति में लोग 'तत्काल' की ओर देखते हैं। वह दिन लद गए जब एक महीने पूर्व लोग आरक्षण करवाते थे। 'आरक्षण' कराने के लिए आगामी योजना बनती है। धैर्य लगता है। दूरदृष्टि लगती है। अब कहां? आज तो वही करेंगे जिसका प्रतिसाद कल मिलेगा।

बदलाव की दुखद मोड़ पर जनतंत्र सिसक–सिसक कर रो रहा है। जो अपवाद है वे भी अफवाह के शिकार हो जाते हैं। अपवाद बचे नहीं, बल्कि पूरी तरह मिट जाए, इसी की ओर लोग लगे रहते हैं। पर क्या इस सच्चाई से इंकार किया जा सकता है कि जीत सत्य की होगी। सत्यमार्ग पर ही चलना होना। हम स्वयं कहते हैं कि अहंकारी रावण का जब अंत हो सकता है तो फिर हम क्या? यह जानते हुए भी हम अहम् से मुक्ति कहां पाते हैं?

आज राजनीति समझने वालों लोगों की आवश्यकता है न कि राजनीति करने वालों की। अधिकता आज उनकी हो गई है जिनकी राजनीतिक समझ नहीं है वे राजनीति करने लगे हैं। फिर जब राजनीति नासमझों के हाथों में चली जाएगी तो फिर आप उनसे समझदारी की राजनीति की अपेक्षा क्यों करते हैं? जैसा बोया है, वैसा ही काटना पड़ेगा।

'स्व–तंत्र' के आगे हमारा गणतंत्र पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। स्थिति बदलनी होगी। ऐसे लोगों को तेजी से राजनीति में शामिल होना होगा, जो राजनीति समझते हैं। विचारधारा समझते हैं। समाजधारा समझते हैं। व्यावहारिकता समझते हैं।

ऐसे लोगों की प्राण–प्रतिष्ठा सभी को मिलकर करनी होगी तब जाकर राजनीति के मायने बदलेंगे और देश जैसा भारत चाहता है वैसा भारत बनेगा अन्यथा तो फिर 'मनरेगा' की राशि के आगे सरपंच, जनपद और जिला न केवल नतमस्तक होंगे बल्कि पूरी तरह से बोली लगाकर राजनीति की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मंडी में खरीद फरोख्त के जिस तरह शिकार हो रहे हैं, वे फिर 'मनरेगा' के रोग से ग्रसित होकर गणतंत्र की जड़ें खोदेंगे और हम और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पायेंगे।■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सांसद हैं)

ऐसे लोगों की प्राण–प्रतिष्ठा सभी को मिलकर करनी होगी तब जाकर राजनीति के मायने बदलेंगे और देश जैसा भारत चाहता है वैसा भारत बनेगा अन्यथा तो फिर 'मनरेगा' की राशि के आगे सरपंच, जनपद और जिला न केवल नतमस्तक होंगे बल्कि पूरी तरह से बोली लगाकर राजनीति की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मंडी में खरीद फरोख्त के जिस तरह शिकार हो रहे हैं, वे फिर 'मनरेगा' के रोग से ग्रसित होकर गणतंत्र की जड़ें खोदेंगे और हम और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पायेंगे।

आधुनिक राजनीति में सिद्धान्तनिष्ठता व शुचिता के राजदूत पं. दीनदयाल उपाध्याय

&fot; i:dk'k folyoh

jk जनीति ने राष्ट्र–जीवन में कुछ ऐसे दोष उत्पन्न कर दिये हैं जो हमारे लिये अभिशाप बन गये हैं। जातिवाद, सिद्धान्तहीनता, पदलोलुपता, वैमनस्यता और अनुशासनहीनता सर्वत्र फैलती जा रही है। इन दोषों से छुटकारा पाने का एकमेव उपाय है कि राजनीति की बागडोर ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो जिनके सबल पग न तो मोह में फंस सकें और न कठिनाईयों में डगमगा सकें वरन् दृढ़ता से एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करते चलें। जो जनता के लिये आदर्श और प्रेरणा प्रस्तुत कर सकें। पं. दीनदयाल उपाध्याय उन आदर्श पुरूषों में से एक थे जिन्होंने शुक्र, बृहस्पति और चाणक्य की भांति आधुनिक राजनीति को शुचि और शुद्धता के धरातल पर खड़ा करने की प्रेरणा दी।

दल के संगठन के नाते दीनदयाल जी जहाँ मृदुभाषी तथा सैद्धान्तिक चर्चा में खुले मन के थे, वहीं सिद्धान्त का आग्रह रखने के बारे में अत्यन्त कठोर भी थे। वे कहा करते थे कि राजनीतिक दल में अनुशासन ऊपर से लादा नहीं जा सकता। आदर्शवाद के साथ सुसंगत आचरण भी दल के अनुशासन का ही एक भाग है।

दल के संगठन के नाते दीनदयाल जी जहाँ मृदुभाषी तथा सैद्धान्तिक चर्चा में खुले मन के थे, वहीं सिद्धान्त का आग्रह रखने के बारे में अत्यन्त कठोर भी थे। वे कहा करते थे कि राजनीतिक दल में अनुशासन ऊपर से लादा नहीं जा सकता। आदर्शवाद के साथ सुसंगत आचरण भी दल के अनुशासन का ही एक भाग है। जनसंघ में आदर्श के अनुरूप आचरण का बड़ा महत्व होता था। दीनदयाल जी अपने समय में सिद्धान्त का कैसा आग्रह रखते थे और अनुशासन किस प्रकार बनाये रखते थे, इनके उदाहरण है 1953 में राजस्थान में जनसंघ ने बिना क्षतिपूर्ति (मुआवजा) दिये जमींदारी समाप्त करने का प्रस्ताव किया था। राजस्थान में उन दिनों जमींदारों और जागीरदारों का राजनीति पर प्रभुत्व था। अतः उनके अनुकूल रहने वाले 6 विधायकों ने जनसंघ की इस भूमिका से विसंगत आचरण किया तो दीनदयाल जी ने उन्हें दल से निकाल दिया। जनसंघ में तब मात्र 2 विधायक बचे, पहले थे भैरोंसिंह शेखावत व दूसरे थे जगतसिंह झाला (बडी सादडी)।

1952 में कानपुर जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय इस नवीन दल के महामंत्री निर्वाचित हुए। अपनी वैचारिक क्षमता को उन्होंने प्रथम अधिवेशन में ही प्रकट किया। कुल 15 प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित हुए, जिनमें से सात अकेले दीनदयाल उपाध्याय ने प्रस्तुत किए। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नवनिर्वाचित महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय से पूर्व परिचित नहीं थे लेकिन कानपुर अधिवेशन में उन्होंने उपाध्याय की कार्यक्षमता, संगठन कौशल एवं गहराई से विचार करने के स्वभाव को अनुभव किया। उसी आधार पर उन्होंने यह प्रसिद्ध वाक्य कहा– ''यदि मुझे पांच दीनदयाल और मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूँ।''

इस नूतन राजनीतिक दल की भूमिका के विषयों में उन्होंने कहा – ''भारतीय जनसंघ एक अलग प्रकार का दल है। किसी भी प्रकार सत्ता में आने की लालसा वाले लोगों का यह झुंड नहीं है ... जनसंघ एक दल नहीं वरन् आन्दोलन है। यह राष्ट्रीय अभिलाषा का स्वयंस्फूर्त निर्झर है। यह राष्ट्र के नियत लक्ष्य को आग्रहपूर्वक प्राप्त करने की आकांक्षा है।''

दीनदयाल उपाध्याय के प्रथम कानपुर, अधिवेशन से ही जनसंघ की कमान संभाल ली थी तथा वैचारिक दृष्टि से जनसंघ के चरित्र को स्पष्ट करने वाला 'सांस्कृतिक पुनर्रुस्थान' प्रस्ताव उन्होंने रखा था। ''जनसंघ का मत है कि भारत तथा अन्य देशों के इतिहास का विचार करने से यह सिद्ध होता है कि केवल भौगोलिक एकता, राष्ट्रीयता के लिए पर्याप्त नहीं है। एक देश के निवासी जन एक राष्ट्र तभी बनते हैं जब वे एक संस्कृति द्वारा एकरूप कर दिये गए हों। हिन्दू समाज को चाहिए कि विदेशी धर्मावलम्बियों को स्नेहपूर्वक आत्मसात कर ले। केवल इस प्रकार साम्प्रदायिकता का अंत हो सकता है और राष्ट्र का एकीकरण तथा दृढ़ता निष्पन्न हो सकती है। उपाध्याय ने मुस्लिम व ईसाइयों के लिए 'हिन्दू समाज' के ही अपने उन 'अंगों' शब्द का प्रयोग किया तथा उन्हें भारतीय जनजीवन का अंग स्वीकार किया है। परोक्षतः यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम समाज को पृथक करने में हिन्दू समाज का कोई अपना भी दोष है जिसे अब ठीक करना चाहिए। अर्थात् उन्हें स्नेह व आत्मीयता प्रदान करनी चाहिए। तभी मुसलमानों की साम्प्रदायिकता की समस्या का समाधान होगा। मुसलमानों अथवा ईसाइयों की अलग संस्कृति और उसके संरक्षण के विचार के तथा अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक विचार को वे राष्ट्र के लिए विभेदकारी तथा साम्प्रदायिक विचार मानते थे।

1964 में राजस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ग्रीष्मकालीन संघ शिक्षा वर्ग उदयपुर में हो रहा था। अपने बौद्धिकवर्ग में उन्होंने कहा ''स्वयंसेवक को राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए जैसे कि मैं हूं।

उनसे सवाल पूछा गया, आप एक राजनीतिक दल के अखिल भारतीय महामंत्री हैं, आप राजनीति से अलिप्त कैसे हैं? दीनदयालजी ने जवाब दिया कि, ''मैं राजनीति के लिए राजनीति में नहीं हूं वरन् मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूँ। राजनीति का संस्कृति से शून्य हो जाना अच्छा नहीं है।''

यह वाक्य पहेली सरीखा था। अतः रात्रि में प्रश्नोत्तर के सत्र में उनसे सवाल पूछा गया, आप एक राजनीतिक दल के अखिल भारतीय महामंत्री हैं, आप राजनीति से अलिप्त कैसे हैं? दीनदयालजी ने जवाब दिया कि, ''मैं राजनीति के लिए राजनीति में नहीं हूं वरन् मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत हूँ। राजनीति का संस्कृति से शून्य हो जाना अच्छा नहीं है।''

अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं मित्रों के दबाब में उन्होंने जौनपुर लोकसभा चुनाव हेतु संयुक्त विपक्ष का प्रत्याशी होना अनमने मन से स्वीकार किया। हालांकि उपाध्याय हारे थे, लेकिन जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोग आज भी उन्हें तथा उस चुनाव को याद करते हैं। उपाध्याय ने इस चुनाव को अपने सिद्धान्तवादी व्यवहार की प्रयोगशाला के रूप में बदल दिया था। पारंम्परिक रूप से जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र, राजपूत व ब्राह्मण जातिवाद के आधार पर लड़े जाने वाले चुनावों की रंगभूमि रहा है। कांग्रेस ने राजपूतवाद का पूरी तरह से सहारा लिया। राजपूतवाद का प्रतिवाद वहां ब्राह्मणवाद से ही किया जा सकता था। स्थानीय लोगों ने जब इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहा, दीनदयाल अपने समर्थकों पर बिगड़े तथा कहा – ''इस प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश की गई, तो मैं चुनावों से हट जाऊँगा। विपक्ष के विषय में उन्होंने कहा, विजयी व्यक्ति को सबसे पहली बधाई मेरी ओर से मिलनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, तुम किसी से भेज दो' मित्रों के आश्चर्य करने पर उन्होंने कहा, 'यह तो हमारी परम्परा है कि विजयी प्रत्याशी को पहली बधाई उसका प्रतिद्वन्द्वी ही दे। आखिर हमारे राजनीति में आने का क्या उपयोग? यदि हम भी लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा का निर्माण नहीं कर पाए।''

जनसंघ एवं संघ के प्रति जवाहरलाल नेहरूजी का व्यवहार कटुतापूर्ण था लेकिन दीनदयालजी ने अनेक अवसरों पर उनके प्रति जो व्यवहार किया वह भी उनके सांस्कृतिक राजदूतत्व को ही रेखांकित करता है। एक अवसर पर उपाध्यायजी ने कहा – ''हमारी पं. नेहरू के साथ चाहे जितनी मतभिन्नता हो और चाहे जितना हम उनकी नीति के विरोध में आन्दोलन चला रहे हों– मैं अपने प्रधानमंत्री को, जिस समय वे विदेशयात्रा पर गए हुए हैं, विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनसंघ की सद्भावनाएं एवं पूर्ण समर्थन इस समय उनके साथ है।''

11 फरवरी 1968 की रात्रि में वे रेल गाड़ी द्वारा लखनऊ से पटना जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह मुगल सराय स्टेशन पर कपड़े में लिपटा हुआ एक शव देखा गया। पहचानने पर पता चला कि यह पार्थिव शरीर पंडितजी का था। चारों ओर शोक की लहर छा गई, इस महान व्यक्ति की हत्या किसने की होगी? आज भी यह प्रश्न अनुत्तरित है। मृत्योपरांत उनकी इस महानता को समर्थकों और विरोधियों दोनों ने समान रूप से स्वीकार किया; उनकी भूरि–भूरि प्रशंसा की तथा मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित की। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री यशवंत राव चव्हाण ने उन्हें 'महान भारतीय' के रूप में श्रद्धांजलि दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाही श्री बाला साहब देवरस ने उन्हें 'आदर्श स्वयंसेवक' के रूप में डॉ. हेडगेवार समान श्रेष्ठ बताया तथा प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री नाथ पै ने कहा कि वह गांधी, तिलक और नेताजी बोस की परम्परा की 'एक कड़ी' थे। साम्यवादी नेता श्री हीरेन मुखर्जी ने श्री उपाध्यक्ष को 'अजातशत्रु' की संज्ञा दी तथा आचार्य कृपलानी ने उन्हें 'देव सम्पदा' की उपमा दी। वास्तव में पं. दीनदयाल उपाध्याय 'महर्षि दधीचि' की भांति राष्ट्र मंदिर के निर्माण में अपने शरीर की एक–एक अस्थि समर्पित कर देने वाले आधुनिक युग के एक महान कर्मयोगी थे। ■

लाल चौक पर तिरंगा न फहराने का फैसला शर्मनाक : भाजपा

Hkkजपा ने गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज न फहराए जाने के फैसले की घोर भर्त्सना की है। पार्टी का कहना है कि अलगाववादी तत्वों के सामने सरकार का यह कायराना समर्पण है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार ने लाल चौक पर झंडा न फहराने का शर्मनाक फैसला लिया और तर्क दिया कि तिरंगा फहराने से अलगाववादियों और अतिवादियों को उकसावा मिलेगा, जो एक अनावश्यक उत्तेजना होगी। श्री जावडेकर ने कहा कि गत 19 वर्षों से सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वहां प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते रहे हैं। यह परिपाटी भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डा. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में अलगाववादियों और पाक प्रायोजित आतंकवादियों की चुनौती के बीच राष्ट्रव्यापी एकता यात्रा शुरू किए जाने के बाद शुरू की गई थी। सुरक्षा बल लाल चौक पर अपना गणतंत्र दिवस समारोह मनाया करते थे और लाल चौक के घंटाघर पर तिरंगा फहराने के बाद मिठाइयां वितरित किया करते थे। भाजपा का कहना है कि सरकार का फैसला सुरक्षा बलों और भारत के लोगों के मनोबल को गिराने वाला है। इस निर्णय को हुर्रियत द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को बंद आयोजित करने की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। ■

बढ़ती महंगाई और लाचार सरकार

vf'ouh egkt u

बढ़ती महंगाई अब आम आदमी की कमर तोड़ रही है। सरकार की ओर से आ रहे बयानों से उसकी लाचारी ही दिखाई देती है। कभी कृषि मंत्री कहते है कि अभी महंगाई और बढ़ेगी, तो वित्त मंत्री महंगाई रोकने के उपायों से आश्वस्त नहीं दिखते। 24 दिसंबर, 2009 को जारी सरकारी आंकड़े खाद्य पदार्थों मे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत की महंगाई दिखाते है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में बाजार में अनाज लगभग डेढ़ गुना, दाल करीब तीन गुना, चीनी लगभग ढाई गुना और खाद्य तेल डेढ़ गुना महंगे हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई के कारण दिहाड़ी मजदूर, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग और उनके परिवार वाले आधा पेट अथवा खाली पेट सोने को मजबूर हैं। दूसरी ओर, दिनोंदिन अमीर हो रहे लोग इस महंगाई के डंक से अछूते हैं।

केंद्र सरकार का कहना है कि यह महंगाई विश्वव्यापी है, इसलिए उसे रोक पाना इतना आसान नहीं है। वह यह भी मानती है कि महंगाई पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों का सहयोग अपरिहार्य है। वित्त मंत्री इस वर्ष आठ प्रतिशत आर्थिक विकास दर प्राप्त करने की बात करते हैं, लेकिन महंगाई रोकने के बारे में कोई ठोस बयान आता नहीं है।

यह बात सही है कि खाद्य पदार्थों मे यह महंगाई विश्वव्यापी है। पिछले कुछ वर्षों मैं वैश्विक स्तर पर खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देश खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाली कृषि भूमि पर जैव ईंधन का उत्पादन करने लगे हैं। खाद्यान्नों का उपयोग भी जैव ईंधन निकालने के लिए किया जाने लगा है। ऐसे में मनुष्य के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता वैश्विक स्तर पर प्रभावित होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस बारे में पहले से आगाह करना शुरू कर दिया था।

लेकिन मौजूदा कृषि संकट के लिए सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं। भूमंडलीकरण और नई आर्थिक नीति के नाम पर कृषि की लगातार अनदेखी की जाती रही। वर्ष 2009–10 के बजट में कृषि को न सिर्फ केवल एक प्रतिशत आबंटित किया गया, बल्कि इस धन का अधिकांश हिस्सा कृषि से जुड़े सरकार के मंत्रालयों एवं अन्य कार्यालयों में कार्यरत अफसरों एवं कर्मियों के वेतनों पर खर्च हो जाता है। सरकार की इस बेरुखी का असर स्वाभाविक ही कृषि उत्पादन पर पड़ा। नतीजतन प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 1990.91 के 186 किलोग्राम सालाना से घटकर 2008–09 में मात्र 148.5 किलोग्राम रह गया।

सरकार को सोचना होगा कि यदि आम जन के लिए दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमतों को नीचे रखना है, तो उसके लिए उसे कृषि विकास के लिए ठोस उपाय करने होंगे। साथ ही, वायदा बाजार पर रोक लगानी होगी।

सरकार का मानना है कि इस बार चावल उत्पादन पिछले वर्ष के 846 लाख टन से घटकर मात्र 716 लाख टन रह जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने का उत्पादन भी 10 प्रतिशत कम रहेगा। इसका सीधा–सीधा असर चीनी के उत्पादन पर पड़ रहा है, जिसकी कीमत पिछले वर्ष की तुलना में ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दाल और खाद्य तेलों के लिए तो हम पहले से ही विदेशों पर निर्भर हैं।

वित्त मंत्री का कहना है कि मौद्रिक नीति द्वारा महंगाई रोकना संभव नहीं है। दरअसल मौद्रिक नीति के जरिये सरकार मुद्रा की आपूर्ति घटाकर मांग पर अंकुश लगाती है। इसके माध्यम से महंगाई को रोकने का प्रयास होता है। वास्तव में 2009.10 के बजट में चार लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक घाटे के कारण सरकार का मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है। इस महंगाई को रोकने के लिए खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, दालों और चीनी की आपूर्ति बढ़ाना ही एकमात्र उपाय हो सकता है। लेकिन वित्त मंत्री शायद भूल जाते है कि आपूर्ति बढ़ाना कोई एक दिन का खेल नहीं है। सरकार यदि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए पुरजोर प्रयास कर ले, तो भी यह उत्पादन एकाएक तो बढ़ने वाला नहीं है। अगर सरकार भारी आयात करके इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाती है, तब भी कीमतों को नीचे लाना तो भी संभव नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कीमतें आसमान छू रही हैं।

यह बात साबित हो चुकी है कि देश में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ाने में वायदा बाजार की भी एक बड़ी भूमिका है। हालांकि सरकार ने चावल, गेहूं और कुछ दालों के लिए वायदा बाजार में रोक लगा रखी है, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि शेष खाद्यान्नों की खरीद–फरोख्त जारी रखने में सटोरियों का ही हित साधन होता है। कई बार सरकारी प्रतिनिधियों की ओर से यह कहा गया कि इससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलता है। लेकिन अभी तक का अनुभव यह बताता है कि इस वायदा बाजार से किसानों को नहीं, बल्कि सटोरियों को फायदा मिला है।

इसमें दो राय नहीं कि वर्तमान महंगाई को रोक पाना सरकार के लिए निकट भविष्य में संभव नहीं। लेकिन सरकार को सोचना होगा कि यदि आम जन के लिए दीर्घकाल में वस्तुओं की कीमतों को नीचे रखना है, तो उसके लिए उसे कृषि विकास के लिए ठोस उपाय करने होंगे। साथ ही, वायदा बाजार पर रोक लगानी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार को अपनी फिजूलखर्ची कम करते हुए बजट घाटे को कम करना होगा, ताकि सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए अतिरिक्त करेंसी नोट न छापने पड़ें।■

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं)

प्रत्यक्ष कर संहिता पर भाजपा का विरोध

गत 02 फरवरी, 2010 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य का पूरा पाठ

dर संहिता–प्रारूप/आयकर अधिनियम न केवल तर्कहीन है बल्कि, यह छोटे कर दाताओं, छोटे व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के लिए कठोर भी है। आज भाजपा नेताओं में वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और कर संहिता के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन की मांग करते हुए विस्तृत ज्ञापन दिया।

सरकार के प्रस्ताव से छोटे और मध्यम आय वर्ग के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा की स्कीमों, जिनमें प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा निगम शामिल हैं, को किए जाने वाले सभी अंशदान कर योग्य हो जाएंगे। कर संहिता प्रारूप सामाजिक – रचनात्मक कार्य करने वाले सांस्कृतिक, खैराती और धार्मिक संस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित करने वाला है।

प्रस्तावित आयकर अधिनियम/कर संहिता प्रारूप पश्चिमी संकल्पना पर आधारित है। मुलाकात करने वाले भाजपा के नेताओं में श्रीमती सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा), श्री अरूण जेटली, नेता प्रतिपक्ष (राज्य सभा), डॉ. किरीट सोमय्या, संयोजक भाजपा प्रत्यक्ष कर संहिता समिति, श्री सुरेन्द्र सिंह अहलुवालिया संसद सदस्य, श्री अनंत कुमार हेगडे, संसद सदस्य, श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य और श्री गोपाल अग्रवाल चर्टर्ड एकाउन्टेंट शामिल थे।

भाजपा 50 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम के पुनर्प्रारूपण/पुनलेखन का स्वागत करती है। यह सरल और सुबोध, प्रगतिशील और 21वीं शताब्दी के विज़न से भरपूर हाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी

1. कर संहिता प्रारूप पश्चिम से लिए गए विचारों और अवधारणाओं का अंधा अनुकरण है। इससे बचत पूंजी निर्माण और सामाजिक सुरक्षा हतोत्साहित होती है।
2. यह खैराती और धार्मिक संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है।
3. ईईई को छोड़कर ईईटी अपनाना आपत्तिजनक है। यह उन वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी करता है, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत है।
4. संहिता क्रूर रिज़ीम स्थापित करने तथा कर अधिकारियों को मनमानी वैवेकिक शक्तियां प्रदान करने का प्रयास करती है।
5. इसके कारण आम आदमी, लघु कर निर्धारिती, जो वैयक्तिक कर दाताओं की कुल संख्या के 90 प्रतिशत है, उनको अधिक कर देना पड़ जाएगा।

भाजपा की मांग :

१. छोटे और मध्यम आय वर्ग को न्याय और संरक्षण

90 प्रतिशत कर दाताओं को कर संहिता प्रारूप के तहत अधिक भुगतान करना होगा। भाजपा महिलाओं के लिए छूट सीमा को 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 3 लाख 50 हजार रूपए और वरिष्ठ नागरिकों को 4 लाख रूपए करने की मांग करती है।

२. बचतों, चिकित्सा व्ययों आदि हेतु प्रोत्साहन

चिकित्सा व्ययों अवकाश यात्रा रियायतों, अवकाश वेतनों आदि से संबंधित छूट को और बचतों पर कर प्रोत्साहन के विद्यमान उपबंधों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

३. सरकारी कर्मचारियों के कब्जे के अधीन मकान/क्वार्टर

सरकारी कर्मचारियों हेतु विहीत मकानों/क्वार्टरों पर कर लगाने संबंधी अव्यावहारिक सुझाव को समाप्त किया जाना चाहिए।

४. कम्पनियों और व्यक्तियों हेतु कर की साझी अधिकतम दर

कर प्रारूप संहिता में व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों के लिए कर की उच्चतम दर 30 प्रतिशत जबकि कम्पनियों के लिए 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। 25 प्रतिशत कर की दर सभी पर लागू होनी चाहिए।

५. आवासीय क्षेत्र के लिए कर संहिता प्रारूप हानिकर है

क. आवासीय ऋण और ब्याज हेतु कर लाभ से संबंधित वर्तमान प्रावधान को बनाए रखा जाना चाहिए तथा उसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

ख. रेंटल हाउसिंग पर काल्पनिक रेंट प्रावधान को हटाया जाना चाहिए।

६. सामाजिक सुरक्षा

निर्वाह निधि, जीवन बीमा पर कर लगाने के सरकारी प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। विद्यमान मॉडल ईईई जारी रखा जाना चाहिए।

७. दीर्घकालीक पूंजीगत लाभ

क. सुरक्षा–संव्यवहार कर समाप्त किया जाना चाहिए

ख. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ तथा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की अवधारणा को जारी रखा जाना चाहिए।

ग. मकान का स्वामी बनने, आवास निर्माण में निवेश करने को प्रोत्साहन और संरक्षण जारी रखना चाहिए।

८. महिला और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रोत्साहन/प्रतिभूत निवेश

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमास प्राप्त 25,000 रूपए तक के ब्याज को कर से माफी होनी चाहिए। इनके लिए कर प्रोत्साहन प्रतिभूत स्कीम तथा वित्तीय विलेखों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

९. लघु और मध्यम उद्यमी

कर संहिता प्रारूप लघु और मध्यम उद्यमियों, जिनमें ठेलेवाले भी शामिल है के लिए कठोर है। 8 प्रतिशत प्रीजम्पटिव प्रोफिट के विद्यमान प्रावधान की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

क. लेखा बहियों और लेखों के रख–रखाव के बारे में तथा 50 रूपए तक की रसीदों के रख–रखाव के बारे में कठोर प्रावधानों की दोबारा जांच की जानी चाहिए।

ख. 20 हजार रूपए की नकद रसीदों/भुगतानों के बारे में प्रावधान को बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया जाना चाहिए।

१०. खैराती और धार्मिक न्यास

क. खैराती और धार्मिक न्यासों पर कर लगाने और उनके रचनात्मक खैराती कार्यकलापों की अनदेखी करने की कर संहिता प्रारूप की अवधारणा अनुचित है। संचय की 15 प्रतिशत की सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए।

११. न्यूनतम एवजी कर

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विषय में परिसंपत्ति पर 2 प्रतिशत कर लगाने का कर संहिता प्रारूप का प्रस्ताव एक बड़ा झटका होगा। लाभ अर्जन पर न्यूनतम एवजी कर की विद्यमान प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए।

१२. अनिवासी भारतीयों को ''अनपेक्षित भारतीय'' समझा गया

कर संहिता प्रारूप में अनिवासी भारतीयों को "अनपेक्षित भारतीय" समझा गया है। 20 से 35 प्रतिशत तक की समान दर से ब्याज और निवेश आय पर कर लगाना आपत्तिजनक है।

१३. स्रोत पर कटौती

कर संहिता प्रारूप में स्रोत पर कटौती के बारे में कठोर प्रावधान किया गया है। यह लघु कर दाताओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बनेगा। इन वर्गों के लिए उचित संरक्षण और छूट की सुविधा दी जानी चाहिए।

१४. कर प्रशासन को मनमानी शक्तियां

कर संहिता प्रारूप में कर प्रशासन को मनमानी, कठोर शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। निजीकरण और उदारीकरण के नाम से सरकार ने इंस्पेक्टर राज चलाने का प्रस्ताव किया है। भाजपा इसका घोर विरोध करती है। ओपनिंग एसेसमेंट आदि के बारे में ऐसी कठोर शक्ति को बढ़ाने के सभी प्रावधानों को समाप्त किया जाना चाहिए।

बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी

संसद और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। भाजपा इस बजट सत्र में लगभग डेढ़ दशक से लटके महिलाओं को आरक्षण देने वाले बिल पारित कराने के लिए सरकार से समयसीमा तय करने की मांग करने की तैयारी कर रहा है। संसद में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के तरकश में महिला बिल ही नहीं बल्कि महंगाई जैसे कई अन्य मुद्दों के तीर मौजूद हैं।

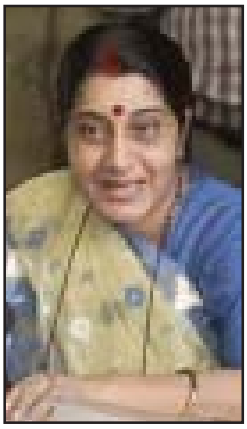

महिला आरक्षण बिल की हालत पर खेद व्यक्त करते हुए एनबीटी लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने इसे बड़ा विरोधाभास बताया कि देश के प्रथम नागरिक के राष्ट्रपति पद समेत चार अहम पदों पर महिलाएं ही बैठी हैं। लेकिन जब भी महिला आरक्षण बिल पारित करने की बात आती है तो इतना विरोध होता है कि बिल पारित ही नहीं हो पाता।

श्रीमती सुषमा स्वराज का कहना था कि मनमोहन सिंह सरकार ने अपनी दूसरी पारी में घोषणा की थी बिल को पारित करने के लिए 100 दिन में प्रभावी उपाय किए जाएंगे लेकिन 100 दिन कब के बीत गए और अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। आगामी बजट सत्र में सरकार से इस बिल को पारित करने के लिए डेडलाइन पूछी जाएगी। यह बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद स्थायी समिति को भेज दिया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। प्रशासनिक समिति को फैसला कर यह बिल लाना है।

श्रीमती स्वराज ने कहा कि देश का मौजूदा राजनीति परिदृश्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तेजी से लगातार बढ़ती महंगाई के कारण विशेष रूप से आम आदमी बेहद त्रस्त और परेशान है। गृहणियां खासतौर पर सरकार को कोस रही हैं। उनके घर का बजट पूरी तरह से चरमरा गया है।

श्रीमती स्वराज ने कहा कि चीन द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण चिंता का विषय है। पाकिस्तान ने 26/11 के दोषियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। इससे भारत–पाकिस्तान संबंधों में यथास्थिति बनी हुई है। सरकार अपने ही अंतर्विरोधों से घिरी है। यूपीए सरकार के पहले चरण के वक्त तो उसके घटक दल उसके लिए तनाव का कारण बनते थे लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी के मंत्री ही प्रधानमंत्री का सिरदर्द बन गए हैं।

बजट सत्र में विपक्ष द्वारा संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों में महंगाई के अतिरिक्त उन्होंने विदेश मंत्रालय पर पूरी चर्चा की मांग किए जाने की बात कहते हुए कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर जस्टिस सगीर अहमद की रिपोर्ट, अल्पसंख्यकों पर रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट, चीन के सीमा अतिक्रमण को लेकर अलग से चर्चा कराए जाने पर जोर दिए जाने का उल्लेख किया।

उनका कहना था कि बजट सत्र में रेल बजट और आम बजट पर चर्चा के अतिरिक्त राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मिलने वाले अवसरों का भी सरकार को घेरने के लिए पूरा लाभ उठाया जाएगा। सरकार की नीतियों पर प्रहार करने के लिए बजट सत्र के दूसरे खंड में चार मंत्रालयों पर होने वाली चर्चाओं के मौके भी मिलेंगे। उन चार मंत्रालयों की पहचान की जाएगी जिन पर चर्चाओं के दौरान सरकार से सवाल पूछे जा सकेंगे।■

भारत को चीन की नई हठधर्मिता के विरुद्ध सतर्क रहना चाहिए : रविशंकर प्रसाद

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संसद सदस्य श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा 29 जनवरी, 2010 को जारी वक्तव्य का पाठ :–

Phन सरकार की शासकीय वेबसाइट पर हाल के इस कथन के साथ कि "किसी भी देश के अंदर या संभावित शत्रुओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रतिशोधी आक्रमण करने के लिए समुद्रपार सैनिक अड्डे स्थापित करना उसका अधिकार है", यह सुस्पष्ट रूप में स्थापित हो गया है कि अब चीन की हठधर्मिता में युद्धकारिता के नए आयाम आ गए हैं। यह अब स्वतः सिद्ध हो गया है कि चीन अब Den-Ziao-Ping की पहले की रणनीति – "जो सर नीचा किए रखो और अपनी शक्ति बढ़ाओ" – की थी को पूरी तरह नकार दिया है। अब चीन अपनी सैनिक महत्वाकांक्षा को खुलेआम दर्शा रहा है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कम्प्यूटरों को हैक करने के प्रयास भी किए गए हैं जैसा कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री नारायणन ने कुछ दिन पहले सार्वजनिक रूप से पुष्टि की थी। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सूचना तंत्र भी सुरक्षित नहीं है तो इससे अधिक चिंता की क्या बात हो सकती है।

स्पष्टतः, इन सब में भारत के लिए गंभीर निहितार्थ छिपा हुआ है। चीन हमारे निकट पड़ोस में अपने भू–राजनीतिक हित अति द्रुत गति से बढ़ा रहा है – चाहे वह मध्य एशिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो और मालदीव हो। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ गठबंधन गंभीर चिंता का कारण है। आज चीन पाकिस्तान के सैनिक हार्डवेयर में 70 प्रतिशत अंशदान करता है। नैवल फ्रिगेट के अतिरिक्त चीन ने पाकिस्तान को लगभग 150 जेएफ 17 फाइटर प्लेन और काफी बड़ी संख्या में जे–10 प्लेन सप्लाई किए हैं। पाकिस्तान के कब्जे में जो क्रूज मिसाइल "बाबर" और बॉलिस्टिक मिसाइल "शाहीन" है, वह चीन की प्रौद्योगिकी पर आधारित है और वह मिसाइल भी प्रौद्योगिकी नियंत्रण रिजीम के उल्लंघन में दी गई है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में कराकोरम राजमार्ग के अलावा, अनेक अन्य सामरिक निमार्ण कर लिए हैं। चीन ने पाकिस्तान – अधिकृत कश्मीर में भी अपनी सुदृढ़ स्थिति दर्ज की है, जोकि विवादित क्षेत्र है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। अरूणाचल प्रदेश पर अति आक्रामक तेवर और लद्दाख में तथा अन्य सीमा क्षेत्रों में उल्लंघन के बढ़ते उदाहरण चीन के कुत्सित इरादे का हिस्सा है।

सरकार, सामरिक समुदाय तथा मिलिटरी थिंक टैंक के बीच चीन की हठधर्मिता से पैदा होने वाली चिंता के बारे में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। इससे इसमें और अधिक वृद्धि होगी कि भारत इस नई हठधर्मिता के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अनिश्चय का शिकार है।

यद्यपि भाजपा टकराव का समर्थन नहीं करती है तो भी पार्टी को आश्चर्य है कि चीन की हठधर्मिता और बढ़ती युद्धकारिता को कम आंकने के जानबूझकर प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। इस दब्बू रवैये से हमारी सामरिक सुरक्षा को भारी क्षति होगी। एक अतिरिक्त चिंता का कारण यह भी है कि नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री मेनन को चीन तथा पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपनाने का पक्षधर समझा जाता है।

सरकार, सामरिक समुदाय तथा मिलिटरी थिंक टैंक के बीच चीन की हठधर्मिता से पैदा होने वाली चिंता के बारे में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। इससे इसमें और अधिक वृद्धि होगी कि भारत इस नई हठधर्मिता के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अनिश्चय का शिकार है। यह आवश्यक है कि हम इस समस्या की पहचान करें, निश्चित समय–सीमा के अंदर सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की परियोजना चलाएं, यथोचित और विश्वसनीय न्यूक्लीयर डेटेरेंट विकसित करें, अपने मिलिटरी हार्डवेयर को समुन्नत करें और पड़ोसी देशों में नई कूटनीतिक पहल करें। प्रधानमंत्री जी को यह सुझाव दिया जाना समीचीन होगा कि वे विद्यमान मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल जाएं, जो दिन–प्रतिदिन अनावश्यक रूप से उलझते जा रहे हैं। भाजपा चीन के साथ बातचीत के विरूद्ध नहीं है, किंतु हमें अपने सामरिक हितों की चिंताओं को कम करके नहीं आंकना चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद सदस्यों और अन्य नेताओं को मिलाकर एक पांच – सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों का दौरा करेगी और भारत में चीनी सेना के बढ़ते अतिक्रमण से पैदा होने वाली धमकी की वास्तविकता के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ■

पाक से वार्ता की पहल कूटनीतिक हार : जावडेकर

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा 05 फरवरी, 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य

पाकिस्तान के साथ सचिव–स्तरीय वार्ता शुरू करने का भारत सरकार का एकतरफा निर्णय दबाव के सामने किया गया घोर समर्पण है और सरकार की पहले की स्थिति का पूरी तरह उलट है। सामान्यतः, विदेश सचिव समग्र वार्ता में शामिल होते हैं तथा वे आतंकवाद पर चर्चा नहीं करते हैं। सरकार की यह पहल बिना किसी कारण के हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह पहल सुरक्षा संबंधी मंत्री–मंडलीय समिति के अनुमोदन के बिना की गई है। इसके कारण गृहमंत्री श्री पी. चिदंबरम के पाकिस्तान के गृहमंत्री के साथ आतंकवाद पर चर्चा करने के प्रयासों को भी धक्का लगेगा। शर्म–अल–शेख़ के बाद यह कदम विदेश नीति की एक और बड़ी भूल साबित होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने पाकिस्तान की उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि वार्ता और आतंक दोनों साथ–साथ चल सकते हैं। हमारी दुर्बलता आतंकवादियों को और अधिक मजबूत करेगी।

भारत की ओर से यह प्रस्ताव अति अनुचित समय पर किया गया है, क्योंकि कल ही मुज़फ्फराबाद में ज़मात–उल–दावा के प्रतिनिधियों के साथ यूनाइटिड जेहादी काउंसिल की मीटिंग में भारत के विरूद्ध जेहाद जारी रखने के इरादों की घोषणा की गई थी। भारत के सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर के कथनानुसार पाकिस्तानी भारी संख्या में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं और वहां पर आतंक का बुनियादी ढांचा अभी भी अक्षुण्ण बना हुआ है। अभी हाल में सीमापार से भारी गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। इन सबसे ऊपर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह कथन रिकार्ड पर है कि वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि 26/11 जैसे आतंकी हमले फिर नहीं होंगे। पाकिस्तान 06 जनवरी, 2004 को दिए गए अपने लिखित वायदे से पहले ही पीछे हट गया है कि वह अपनी भूमि का प्रयोग आतंकवादियों को नहीं करने देगा। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है।

इस परिप्रेक्ष्य में, भारत की घोषित नीति और संसद को दी गई उस वचनबद्धता को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि जब तक पाकिस्तान 26/11 के आतंकवादियों के विरूद्ध ठोस कार्रवाई नहीं करता है और आतंकी ढांचे को नष्ट नहीं करता है तब तक उसके साथ समग्र वार्ता शुरू नहीं की जानी चाहिए। विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा ने पाकिस्तान से "ठोस कार्रवाई" की बजाय "कुछ कदम उठाए" जाने की आशा करके भारत की स्थिति को पहले ही कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान ने वह हासिल कर लिया है, जो उसने चाहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने पाकिस्तान की उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि वार्ता और आतंक दोनों साथ–साथ चल सकते हैं। हमारी दुर्बलता आतंकवादियों को और अधिक मजबूत करेगी।

भाजपा सरकार की इस कार्रवाई की भर्त्सना करती है और इस अचानक काया–पलट के बारे में प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करती है।

आतंकवाद को महिमामंडित कर रहे हैं कांग्रेसनेता

श्री दिग्विजय सिंह का यह खुलासा कि वे श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की सहमति से आज़मगढ़ गए थे इतना अधिक गंभीर है, जिसमें स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। कांग्रेस ने, वास्तव में, श्री दिग्विजय सिंह को आज़मगढ़ भेजकर आतंकवाद को सम्मान प्रदान किया है। वोट बैंक की इस राजनीति से देश के आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों को गहरी क्षति पहुँचेगी। जब उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की पुलिस ने इंडियन मुज़ाहिदीन के आतंकवादी शहज़ाद आलम को गिरतार किया था, तब उसने बाटला हाउस शूट आउट के कंपकंपी पैदा करने वाले ब्यौरों का खुलासा किया था। इस मौके पर इस तरह की राजनीतिक कवायद से सुरक्षा बलों का मनोबल और अधिक गिर जाएगा और चालू तफतीशों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री दिग्विजय सिंह ने आज़मगढ़ में जाकर सुपर इन्वेस्टिगेटर की भूमिका ग्रहण कर ली है और स्वयंघोषित तथ्य अन्वेषण मिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उनकी करतूतों ने बाटला हाउस मुठभेड़ के बारे में अनावश्यक संदेह पैदा कर दिए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की इस पहल की घोषणा के बावजूद किया गया है कि बाटला हाउस मुठभेड़ 'वास्तविक' थी। आज़मगढ़ में किया गया यह अनिष्ट कांग्रेस की अल्पसंख्यक मतों को प्राप्त करने और आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाने की हताशा का सूचक है। श्री दिग्विजय सिंह के प्रयास दर्शाते हैं कि आतंकवाद विरोधी उपाय अल्पसंख्यक विरोधी है। यह कांग्रेस की निकृष्टतम साम्प्रदायिक राजनीति है और स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भी अन्याय है।

भारतीय जनता पार्टी इस निकृष्टतम साम्प्रदायिक और वोट बैंक राजनीति की भर्त्सना करती है और श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी से इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग करती है। ■

जनता द्वारा सौंपी गयी जवाबदेही समर्पण भाव से पूर्ण करें : लालकृष्ण आडवाणी

Hkkरतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपप्रधानमंत्री और भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना के पूर्व सरसंघचालक गुरूजी आश्वस्त हो गये थे। डॉ. मुखर्जी के विचार दर्शन और राजनैतिक दृष्टि में उन्हें राष्ट्रवाद से प्रेरित भारत की तस्वीर दिखायी दी और गुरूजी ने भारतीय जनसंघ के लिये अपने विश्वस्थ साथी दे दिये। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय के आचरण, व्यवहार और विचार धारा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कानपुर अधिवेशन में कहा था कि यदि उन्हें पंडित दीनदयाल जैसे आधा दर्जन विश्वस्थ साथी मिल जाते है तो वे देश का नक्शा बदल देंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भोपाल में 31 जनवरी, 2010 को आयोजित पार्टी के नवनिर्वाचित स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, महापौर, सभापति, अध्यक्ष और पार्षदों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए पूरे समर्पण के साथ जुटें। राजनीति में व्याप्त हो रहा भ्रष्टाचार एक कलंक है इसे समाप्त करने की शुरूआत हमें स्थानीय निकायों से ही करना होगी। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक संजर, नगरीय निकायों के पदाधिकारी आलोक शर्मा, सूर्यप्रकाश तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने आडवाणी जी का स्वागत किया। महापौर कृष्णा गौर ने आडवाणीजी को पुष्पगुच्छ और शॉल भंजिका की प्रतिकृति भेंट की। कैलाश जोशी ने अपने उदघाटन भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जनसेवा के माध्यम से समाज में सुखद परिवर्तन लाना है। सत्ता हमारा मिशन नहीं है। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने काम से जनता में पार्टी की और अपनी पहचान बनाएं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम सफल हो रहे है। जिनसे समाज के हर वर्ग से पार्टी संगठन का संवाद हो रहा है और उन्हें इन कार्यक्रम से सुकून मिल रहा है। उज्जैन में रविदास कुंभ के आयोजन को उन्होंने बेहद उपयोगी बताया और भूरि–भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को समृद्ध बनाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को चरितार्थ करना है इसके लिए लगातार जनोन्मुखी कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे है। आवश्यकता इस बात की है कि जो कार्यक्रम हाथ में लिया जाता है उसे निरंतरता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए और लक्ष्य हासिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में पहुंचकर पार्टी विचारधारा को आगे बढ़ाते है, लेकिन नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत में जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी विशेष प्रकार की होती है उन्हें अपने आचरण और ईमानदारी से जनता के सामने उदाहरण बनना पडता है। यदि हमें व्यवस्था बदलना है तो अपने को बेहतर पेश करना होगा। हमारी छोटी सी भूल पार्टी का बड़ा नुकसान करती है। जनता ने जिन आशाओं के साथ हमें चुनकर भेजा है यदि हम विफल रहते है तो इसका खामियाजा संगठन को भुगतना पडता है।

हमेशा डॉ. मुखर्जी के समर्पण और पं. दीनदयाल उपाध्याय के सादे जीवन उच्च विचार और सेवा भावना को अपने जहन में रखें।

आडवाणी जी ने कहा कि आजादी के बाद कुछ दिन तक लोगों के जीवन में शुचिता रही है किंतु धीरे धीरे नौकरशाही और बाद में राजनीति में भी खोट आने लगी है जिससे जनता का विश्वास आहत हो रहा है। हमें अपने आचार व्यवहार और पार्टी की विचारधारा, जीवनदर्शन, मूल्य आधारित राजनीति का उदाहरण पेश करना है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध मोर्चा खोलना है और इस लडाई को निकायों के स्तर से आरंभ करना है। सुशासन देना हमारी पहली जिम्मेदारी है।

श्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने सम्मेलन को

संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय लोकतंत्र की पाठशाला है यदि हमने सेवा का भाव लेकर ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य अदा किया तो कोई भी शक्ति हमें सांसद, विधायक और नगरीय निकाय में चुनाव जीतने से रोक नहीं सकती है। आपने आडवाणीजी का आभार प्रदर्शित करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन हमेशा सहजता से उपलब्ध होता है और उनका मार्गदर्शन ही संगठन के लिये बडी पूंजी है।

आपने आडवाणी जी को बताया कि नगरीय निकाय के चुनाव के समय तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन जिस समर्पण के साथ पार्टी संगठन और कार्यकर्ता स्थानीय निकाय के चुनाव में कूद पड़े उससे पार्टी को भारी विजय प्राप्त हुई। विधानसभा, लोकसभा के बाद नगरीय निकायों के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली है। कांग्रेस के सभी दावे धूल धूसरित हो गये है। नगर निगम चुनाव में 13 में से 8, नगर पालिका चुनाव में 191 में से 91 निकाय भाजपा के कब्जे में आये है। प्रदेश के कुल पार्षद 5059 में से 2396 भाजपा के विजयी हुए है। नगर निगम के पार्षद और नगर पालिका, नगरपंचायत के प्रतिनिधि स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग से भी 80 पार्षद जीतकर आये है जिससे हमारे बढ़ते जनाधार का सबूत मिलता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पार्टी का परचम फहराया है। राष्ट्र के पुनर्निमाण और जनता जनार्दन की सेवा के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए है। शिवराजसिंह चौहान ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आगाह किया कि राजनीति की राहे रपटीली होती है वे संभल कर चलें। स्वार्थ के लिए राजनीति न करें उन्हें राह से भटकाने के लिए तमाम लोग आयेंगे लेकिन वे अपने आचार विचार की शुचिता पर अटल रहे।

उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हमेशा निर्गुट रहने, अहंकार मुक्त रहने, धैर्यवान और उत्साहित बने रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के पीछे हमारी कल्पना गरीबी का उन्मूलन करना, अंतिम व्यक्ति के आंसू पोछना और प्रदेश का नक्शा बदलना है। नगरीय निकाय के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोडने का जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि हमारे सामने विकास का खाका तैयार है। नगरीय निकायों का विकास अब निर्वाचित प्रतिनिधियों को करना है। उनकी जिम्मेदारी तभी सफल होगी जब वे अतिरिक्त उत्साह के साथ जनसेवा में जुटेंगे।

प्रदेश संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय चुनाव में उन्हें विजयी बनाकर जनता ने अपना भविष्य उनके हाथ में सौंपा है। उन्हें अपनी कार्यकुशलता से विकास को गति देना है। आपने आग्रह किया कि वे निकाय में पद पर आने के बाद अपने को पार्टी से बडा न समझे। उनकी जीत के पीछे पार्टी की मेहनत और कार्यकर्ताओं का समर्पण है। पार्टी के साथ विकास का कार्यक्रम बनाएं और उसे पूरा कर स्थानीय विकास में जनाकांक्षा का रंग भरे। सामाजिक उत्सवों, सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लें क्योंकि ऐसा करने से उनका संवाद विस्तृत होता है और वे समाज के हर वर्ग से जुड जाते है। स्थानीय शासन मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने कहा कि नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों का सम्मेलन, सांसद और विधायकों के किसी भी सम्मेलन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बाद स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार का रूप लेता है। स्थानीय निकाय अधिक गतिशीलता और क्रांतिकारिता के साथ प्रदेश में कार्य करेंगे। इसके लिए उन्हें मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, तकनीकी सलाह उपलब्ध की जायेगी। संभागीय स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित किए जायेंगे।

श्री बाबूलाल गौर ने प्रदेश में नगरीय निकायों के क्षेत्र में विकास के लिये चल रही केन्द्र प्रवर्तित और राज्य सरकारों की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि विकास में धन का अभाव बाधा नहीं बनने दिया जायेगा किंतु प्रतिनिधियों को उत्साह के साथ पूरा समय नगरीय निकाय के कामों में देना होगा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को जनअपेक्षा के अनुसार विकसित करने के लिए स्टाफ में वृद्धि की जायेगी। 50 हजार कर्मचारियों की इसी वर्ष भर्ती की जायेगी। साथ ही नगरीय निकाय में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी से लेकर सीएमओ और आयुक्त तक को ड्रेस कोड के अंतर्गत लाया जायेगा।

इससे उन्हें हमेशा अपनी जवाबदेही का अहसास होगा। सम्मेलन के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, प्रदेश सह संगठन महामंत्री भगवतशरण माथुर, अरविन्द मेनन, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेन्द्रसिंह सिसोदिया, अनिल माधव दवे, प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सिंह, नंदकुमारसिंह चौहान, फग्गनसिंह कुलस्ते, प्रदेश मंत्री अजयप्रताप सिंह, रामेश्वर शर्मा, राजेन्द्र पाण्डे, सरिता देशपाण्डे, गोविन्द मालू सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक ने कार्यक्रम में भाग लिया और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्र में विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा की।■

आजादी के बाद कुछ दिन तक लोगों के जीवन में शुचिता रही है किंतु धीरे धीरे नौकरशाही और बाद में राजनीति में भी खोट आने लगी है जिससे जनता का विश्वास आहत हो रहा है। हमें अपने आचार व्यवहार और पार्टी की विचारधारा, जीवनदर्शन, मूल्य आधारित राजनीति का उदाहरण पेश करना है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध मोर्चा खोलना है और इस लडाई को निकायों के स्तर से आरंभ करना है। सुशासन देना हमारी पहली जिम्मेदारी है।

छत्तीसगढ़ : बढ़ते कदम विकास के

पिछले पन्द्रह वर्ष के कार्यों को सिर्फ पांच वर्ष में पूर्ण करने के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के घोषित इरादे से यह जाहिर हो जाता है कि राज्य के तेज विकास के लिए वह गांव, गरीब और किसानों सहित सबको साथ लेकर मंजिल की ओर पहले से भी ज्यादा तेज कदमों से चलना चाहते हैं। उनके इस नेक इरादे में छत्तीसगढ़ को विकास की नई बुलंदियों तक जल्द से जल्द पहुंचाने की व्याकुलता भी साफ झलकती है। इस दिशा में उनकी लगातार जारी कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। उनके सहृदय, संवेदनशील, कल्पनाशील और पारदर्शी नेतृत्व में राज्य को विगत छह वर्ष में जनता की सामाजिक–आर्थिक बेहतरी के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नयी उपलब्धियां मिली हैं। प्रदेश की जनता ने उनकी लोक हितैषी योजनाओं पर लोकप्रियता की मुहर लगाकर यह साबित कर दिया है। उनकी पहली पारी के पांच वर्ष और दूसरी पारी में भी प्रदेश की अब तक की विकास यात्रा समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के लिए कामयाबियों से परिपूर्ण कही जा सकती है। इस अवधि में राज्य में पक्के वादे और नेक इरादे के साथ योजनाओं और उपलब्धियों की एक लम्बी श्रृंखला लगातार बनती चली गई है, जिसकी बिन्दुवार झलक यहां प्रस्तुत है :–

- **गरीबों के लिए और भी सस्ता हुआ चावल :-** प्रदेश के लगभग 37 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत जुलाई 2009 से सिर्फ एक रूपए और दो रूपए किलो में मिलने लगा है हर महीने 35 किलो चावल, जो उन्हें अब तक केवल तीन रूपए किलो में दिया जा रहा था। अब इनमें से अंत्योदय श्रेणी के सात लाख 19 हजार परिवारों को सिर्फ एक रूपए और शेष लगभग तीस लाख गरीब परिवारों को केवल दो रूपए किलो में मिल रहा है चावल।

- **नि:शुल्क नमक :-** इन सभी परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से विगत लगभग पांच वर्ष तक हर महीने सिर्फ 25 पैसे किलो में दो किलो आयोडिन नमक 'छत्तीसगढ़ अमृत' उपलब्ध कराने के बाद अब उनके राशन कार्डों पर हर महीने यह नमक नि:शुल्क देने की व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2009–10 के छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में गरीबों के चावल और नमक के लिए 1458 करोड़ रूपए का प्रावधान।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जन-भागीदारी :-** राज्य की दस हजार 455 उचित मूल्य दुकानों का संचालन सहकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, स्व–सहायता समूहों और वन प्रबंध समितियों के माध्यम से। जनता की सुविधा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए राज्य शासन द्वारा देश की पहली जनभागीदारी वेबसाईट की स्थापना।
- राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित छत्तीसगढ़ :– राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्मान – 'गोल्ड एवार्ड'। ग्रामीण क्षेत्रों के हाट–बाजारों में उजियारा योजना के तहत बिना राशन कार्ड प्रतिव्यक्ति दो लीटर मिट्टी तेल उचित मूल्य पर प्राप्त करने की सुविधा। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिए ई–एग्रीकल्चर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए ई–इण्डिया एवार्ड। धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए समितियों के कम्प्यूटरीकरण पर छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया ई–गवर्नेन्स का राष्ट्रीय पुरस्कार।
- **पहुंच विहीन गांवों में अनाज बैंक :-** भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में स्थित लगभग दो हजार गांवों में गरीबों की सुविधा के लिए अनाज बैंकों की स्थापना।
- प्रदेश के लगभग साढ़े पांच लाख लघु और सीमांत किसानों को 118 करोड़ रूपए के ऋणों के बोझ से मिली मुक्ति।
- सिंचाई टैक्स की बकाया 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर किसानों को शेष 50 प्रतिशत टैक्स से छुटकारा।
- **तीन प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण:-** मेहनतकश किसानों को सिर्फ तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कृषि ऋण की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सहकारी समितियों में कृषि ऋण पर ब्याज दर को 16 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया। कृषि ऋण की सीमा भी तीन लाख रूपए से बढ़ाकर पांच लाख रूपए की गई। चालू खरीफ वर्ष 2009–10 में किसानों को एक हजार करोड़ रूपए का ऋण देने का लक्ष्य।

- **किसानों को मिला मेहनत का वाजिब मोल :-** समर्थन मूल्य नीति के तहत प्राथमिक सहकारी समितियों में विगत पांच वर्ष में किसानों से खरीफ के दौरान लगभग एक करोड़ 71 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी और उन्हें 11 हजार 253 करोड़ 39 लाख रूपए का भुगतान। इसमें से वर्ष 2004–05 में 1651 करोड़ 90 लाख रूपए का 28 लाख 86 हजार मीटरिक टन, वर्ष 2005–06 में 2089 करोड़ 99 लाख रूपए का 35 लाख 87 हजार मीटरिक टन, वर्ष 2006–07 में 2200 करोड़ 47 लाख रूपए का 37 लाख 08 हजार मीटरिक टन, वर्ष 2007–08 में 2074 करोड़ 56 लाख रूपए का 31 लाख 51 हजार मीटरिक टन और वर्ष 2008–09 में 3236 करोड़ 45 लाख रूपए का 37 लाख 59 हजार मीटरिक टन धान समितियों में खरीदा गया। इस वर्ष अब तक 38 लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा अग्रणी राज्य।
- **वनवासी-ग्रामीणों को रोजगार :-** प्रदेश के सभी 32 वनमंडलों में 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों और सात हजार 887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वनवासी ग्रामीणों के लिए रोजगार की बेहतर व्यवस्था। लघु वनोपज समितियों में सदस्य के रूप में शामिल 12 लाख 65 हजार परिवारों को हर साल तेन्दूपत्ता और साल बीज जैसे लघु वनोपजों के संग्रहण में मौसमी रोजगार। तेंन्दूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2008 से 500 रूपए से बढ़ाकर 600 रूपए और वर्ष 2009 में 650 रूपए प्रतिमानक बोरा निर्धारित। वर्ष 2008 में 13 लाख 78 हजार मानक बोरा और वर्ष 2009 में 14 लाख 62 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित। तेन्दूपत्ते से वनवासियों को वर्ष 2008 में 82 करोड़ 77 लाख रूपए और इस वर्ष 2009 में 95 करोड़ रूपए का पारिश्रमिक मिला। साल बीजों की संग्रहण दर वर्ष 2007–08 के पांच रूपए के मुकाबले इस वर्ष बढ़ाकर 10 रूपए प्रतिकिलो तय किया गया। साल बीज संग्रहण में इस वर्ष वनवासियों को 85 करोड़ रूपए से अधिक राशि की आमदनी। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में 27 लाख 63 हजार परिवार सदस्य के रूप में शामिल। वनों के रख–रखाव में जनभागीदारी को बढ़ावा देना इन समितियों का उद्देश्य। इन समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा और वन संवर्धन के रोजगार मूलक कार्यों सहित ग्राम विकास के लिए स्टाप डेम, पुल–पुलिया, आंगनबाड़ी भवन निर्माण और सड़क निर्माण तथा मरम्मत जैसे अनेक रोजगार मूलक कार्य। तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को तीन वर्ष में 36 लाख जोड़ी से अधिक चरण पादुकाएं निःशुल्क वितरित।
- **वनवासियों को वन अधिकार पत्र :-** अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन क्षेत्र में वर्षों से रह रहे लगभग एक लाख 28 हजार निवासियों को अधिकार पत्र वितरित, जबकि एक लाख 50 हजार से अधिक वनवासियों को अधिकार–पत्र देने का कार्य भी बहुत जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य।
- **वनवासियों को मिली मुकदमों के बोझ से मुक्ति :-** भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत सामान्य वन अपराधों के विगत वर्ष 1952–53 से 30 जून 2004 तक लंबित दो लाख से अधिक प्रकरणों को समाप्त कर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के वनवासी परिवारों को मुकदमों के बोझ से दिलाई गई मुक्ति। लगभग दो लाख 20 हजार वनवासी लाभान्वित। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2005 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। इन सभी प्रकरणों में वनवासियों को लगभग 12 करोड़ 76 लाख रूपए के जुर्माने की राशि भी मिली मुक्ति।
- **शुद्ध पेयजल की बेहतर व्यवस्था :-** राज्य की 72 हजार 775 बसाहटों में से 71 हजार 714 बसाहटों में अर्थात् 98.54 प्रतिशत बसाहटों में की गई शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। राष्ट्रीय मापदण्ड प्रति 250 व्यक्तियों के मुकाबले राज्य में प्रति 88 व्यक्तियों पर एक हैन्ड पम्प की सुविधा उपलब्ध। नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजनाओं के लिए राज्य शासन द्वारा 30 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था, जो देश में सर्वाधिक है।
- **सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान :-** राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के दस लाख से अधिक घरों में पक्के शौचालयों का निर्माण पूर्ण।
- **देश का पहला बिजली कटौती मुक्त राज्य :-** छत्तीसगढ़ बना जनवरी 2008 से देश का पहला और इकलौता विद्युत कटौती मुक्त राज्य। अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबी रेखा श्रेणी के लगभग नौ लाख से अधिक एकलबत्ती कनेक्शन धारक परिवारों को हर महीने 50 रूपए की तीस यूनिट बिजली निःशुल्क। इसके लिए राज्य शासन द्वारा हर महीने खर्च किए जा रहे हैं पचास करोड़ रूपए। अब इस एकलबत्ती योजना में गरीबों को तीस यूनिट की खपत सीमा में तीन बत्ती लगाने की भी सुविधा।
- **सबसे सस्ती बिजली-** सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली का सम्मान :– केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कोरबा पश्चिम ताप विद्युतगृह में उत्पादित बिजली की उत्पादन लागत देश में सबसे कम 87 पैसे प्रति यूनिट। यह बिजलीघर 98.7 प्रतिशत पीएलएफ के कारण देश के सर्वश्रेष्ठ बिजलीघर के रूप में सम्मानित।
- **विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की सार्थक पहल :-** राज्य की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता छह हजार 125 मेगावाट। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनी की एक हजार 925 मेगावाट, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की तीन हजार 100 मेगावाट और निजी क्षेत्र के संयंत्रों की एक हजार 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 45 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता की बिजली परियोजनाओं के लिए निजी कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर किए गए हस्ताक्षर। इनमें से 21 हजार मेगावाट की परियोजनाओं के

लिए क्रियान्वयन अनुबंध पूर्ण। इन परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने पर वर्ष 2012–13 तक प्रदेश में पैदा होगी 16 हजार मेगावाट बिजली। एन.टी.पी.सी. द्वारा रायगढ़ जिले के ग्राम लारा में चार हजार मेगावाट के विशाल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य शासन के साथ विगत 12 जुलाई 2009 को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे के उपस्थित में हुआ एमओयू।

- **सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत गृह :-** भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए गोल्ड शील्ड से सम्मानित किया गया है।
- **बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सम्मान :-** जनसंख्या नियंत्रण और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सेवाओं सहित टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, कुपोषण मुक्ति, शिशु मृत्यु दर में कमी, स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति और महिला साक्षरता जैसे 14 विभिन्न मानकों में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान के रूप में मिला देश का प्रतिष्ठित जे.आर.डी. टाटा मेमोरियल पुरस्कार।
- **जीवन-दीप अस्पताल सुधार योजना:-** सरकारी अस्पतालों के प्रबंधन में व्यापक जन–भागीदारी के लिए 861 जीवन–दीप समितियों का गठन।
- **मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना :-** राज्य की ग्रामीण बसाहटों में लगभग 60 हजार स्थानीय महिलाओं को मितानिन के रूप में प्रशिक्षित कर सामान्य बीमारियों के प्रारंभिक इलाज का दायित्व सौंपा गया। उन्हें मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना के तहत पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयां भी उपलब्ध करायी गयी ताकि वे जरूरतमंद मरीजों का इलाज कर सकें।
- **संजीवनी कोष गरीबों के लिए बनी संजीवनी :-** गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए आर्थिक सहायता की अभिनव योजना। जनवरी 2004 से जून 2009 तक दो हजार 125 मरीजों को लगभग 23 करोड़ रूपए की मदद।
- **दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना:-** ग्रामीण क्षेत्रों में आवासविहीन गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए प्रति परिवार 900 वर्गफुट भूमि वितरण का कार्य जारी। इस योजना के तहत 88 हजार ग्रामीणों को आवासीय भूमि देने का लक्ष्य। अब तक 46 हजार 757 परिवारों के लिए पट्टे तैयार और उनमें से 43 हजार से अधिक परिवारों को वितरित।
- वर्ष 1997 तक नियुक्त और पात्रता रखने वाले लगभग 15 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नौकरी में लेकर उनके परिवारों को दी गई एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी।
- राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र के समान छठवें वेतनमानों का समुचित लाभ दिलाने वित्त विभाग द्वारा संकल्प घोषित। नया वेतनमान निर्धारित होने तक कर्मचारियों को एक सितम्बर 2008 से मूलवेतन और महंगाई वेतन की 20 प्रतिशत राशि तथा पेंशनरो को मूल पेंशन और महंगाई पेंशन की 10 प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के रूप में देने की घोषणा।
- **राज्य कर्मचारियों को छठवां वेतनमान:-** प्रदेश सरकार के लगभग दो लाख कर्मचारियों को दिया जा रहा है केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर छठवां वेतनमान। बजट में एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- वेतनभोगियों को वृत्ति कर (प्रोफेशनल टैक्स) से पूर्णतः मुक्ति। अब वर्ष 2009–10 के बजट में दस लाख रूपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों को भी वृत्ति कर के दायरे से पूर्णतः मुक्त किया गया। इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य के लगभग दस हजार छोटे व्यापारियों को मिलेगी राहत।
- **गरीबों के जीवन में नवा अंजोर (नई रोशनी) :-** ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य के 40 विकासखण्डों के दो हजार गांवों में चल रही है नवा अंजोर परियोजना। इसके माध्यम से अब तक एक लाख से अधिक परिवारों को हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, लघु व्यवसाय, लघु सिंचाई आदि के लिए सामूहिक रूप से लगभग 179 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता। परियोजना के तहत इन परिवारों के बीस हजार 989 समहित समूहों को गठन।
- **महिलाओं के हित में सार्थक कदम :-** पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण। महिलाओं के नाम से भूमि खरीदने पर पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट। छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की विवाह योग्य चौदह हजार से अधिक बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन। ऐसे प्रत्येक विवाह के लिए पांच हजार रूपए का खर्च राज्य सरकार की ओर से अब तक सोलह हजार से अधिक कन्याओं के विवाह सम्पन्न। इसमें से चार हजार रूपए का सामान कन्या को और शेष एक हजार रूपए आयोजन में व्यय के लिए। ' महिलाओं को भूमि खरीदी के पंजीयन पर शुल्क में दो प्रतिशत की विशेष छूट। ' महिला उत्पीड़न की रोकथाम और महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए टोनही प्रताड़ना निवारण कानून 2005 लागू। किसी भी महिला को टोनही कहने या टोनही के नाम पर प्रताड़ित करना गैर–जमानती/संज्ञेय अपराध। अधिकतम पांच वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान। ' त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूहों को कारोबार के लिए सिर्फ साढ़े छह प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा। ' रसोई गैस कनेक्शन पर महिलाओं को राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में एक सौ रूपए की विशेष छूट।
- **तीन विशेष प्राधिकरणों का गठन :-** आदिवासी बहुल क्षेत्रों और अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और वहां विकास कार्यों में और भी अधिक तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन विशेष

प्राधिकरणों का गठन। सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के जरिये राज्य के पिछड़े इलाकों में विकास की गति बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कामयाबी। प्राधिकरणों की विभिन्न बैठकों में जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श कर लिए जाते हैं जरूरी फैसले। विगत पांच वर्ष में तीनों प्राधिकरणों द्वारा कुल पौने चार सौ करोड़ रूपए से अधिक राशि के ग्यारह हजार 392 विकास कार्य मंजूर। सरगुजा प्राधिकरण द्वारा तीन हजार 282 कार्यों के लिए 134 करोड़ 40 लाख रूपए, बस्तर प्राधिकरण द्वारा चार हजार 545 कार्यों के लिए 145 करोड़ रूपए और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा तीन हजार 565 कार्यों के लिए 96 करोड़ रूपए मंजूर।

- आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में आश्रम शालाओं की संख्या 516 से बढ़कर एक हजार 024 हो गई। इस दौरान 556 नये छात्रावास खोले गए। इन सभी आश्रम–छात्रावासों में एक लाख 40 हजार से ज्यादा छात्र–छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ मिली शिक्षा की बेहतर व्यवस्था।
- **स्कूल शिक्षा का विस्तार :-** सर्वशिक्षा अभियान के तहत कक्षा आठवीं तक सभी लगभग 50 लाख स्कूली बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण। राज्य शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की एक हजार 370 छोटी बसाहटों में बच्चों को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने ज्ञान–ज्योति विद्यालयों की स्थापना। राज्य के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लगभग सभी बच्चों का प्राथमिक शालाओं में नामांकन। इसके अलावा 93 विकासखण्डों में कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्ययनरत बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा और कम्प्यूटर सुविधा से सुसज्जित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का संचालन। स्कूली बच्चों की मध्याह्न भोजन योजना में प्रति छात्र राशि दो रूपए 50 पैसे से बढ़ाकर तीन रूपए करने का निर्णय और इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान। चालू वित्तीय वर्ष में ही एक सौ उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए का प्रावधान। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विगत पांच वर्ष में 55 हजार शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति। अब स्कूल शिक्षा विभाग के लिए पुनरीक्षित सेट–अप स्वीकृत कर उसमें 35 हजार अतिरिक्त पद शामिल।
- **सरस्वती सायकल प्रदाय योजना :-** हाई स्कूल स्तर (कक्षा नवमी–दसवीं) की अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग की सभी बालिकाओं और पिछड़े वर्ग के अंतर्गत गरीबी रेखा श्रेणी की बालिकाओं को निःशुल्क सायकल। अब तक एक लाख 50 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित। स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा योजना का संचालन। चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्कूलों में सरस्वती सायकल प्रदाय योजना के लिए 26 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान। इसके अलावा योजना का विस्तार करते हुए गरीबी रेखा श्रेणी की सभी छात्राओं को इसमें लाभान्वित करने का निर्णय।
- **उच्च शिक्षा की बढ़ती सुविधाएं :-** विगत छह वर्ष में राज्य में छह नये विश्वविद्यालयों की स्थापना – स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (भिलाई नगर), पंडित सुन्दरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी (बिलासपुर), कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (रायपुर), छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (रायपुर), बस्तर विश्वविद्यालय (जगदलपुर) और सरगुजा विश्वविद्यालय (अम्बिकापुर)। इन्हें मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में कुल ग्यारह विश्वविद्यालय। ' बस्तर (जगदलपुर) में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ। रायगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए प्रक्रिया प्रगति पर। राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (रायपुर) परिसर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी) की स्थापना। गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को मिला केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा।
- **छत्तीसगढ़ी को मिला राजभाषा का राजमुकुट :-** राज्य सरकार द्वारा आम जनता की बोल चाल की भाषा छत्तीसगढ़ी को दिया गया राजभाषा का दर्जा। इसके समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया।
- **सड़क नेटवर्क का निरन्तर विस्तार :-** राज्य में अच्छी सड़कों का जाल बिछाने का अभियान निरन्तर जारी। विगत पांच वर्षो में लगभग 27 हजार 462 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण, नवीनीकरण तथा चौड़ीकरण किया जा चुका है। इसके अलावा 476 बड़े और 74 मध्यम पुलों सहित 11 हजार से अधिक छोटी पुलियों का निर्माण पूर्ण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों और 13106 पुल–पुलियों का निर्माण करते हुए तीन हजार 797 ग्रामीण बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा गया।
- **विशेष पिछड़ी जनजातियों को आवास:-** विशेष पिछड़ी पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, कमार तथा बैगा जनजातियों के समस्त आवासहीन परिवारों को नए आवास उपलब्ध कराने की देश में एक अभिनव पहल। इनके लिए लगभग 28 करोड़ रूपये की लागत से सात हजार 926 आवास निर्माण की योजना।
- **नई पीढ़ी के लिए रोजगार के बेहतर अवसर :-** विगत पांच वर्ष में कम से कम एक लाख युवाओं को शिक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी, उप अभियंता, संविदा सहायक प्राध्यापक और पटवारी आदि के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के साथ मिला रोजगार और जनता की सेवा का अवसर। ■

सेवोन्मुख प्रगति पथ पर अग्रसर मध्यप्रदेश

Hkjr pnz uk;d

Hkk रतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विकास तक निरंतर संगठन की अपनी विशिष्टता के पीछे इसकी कार्यकर्ता आधारित प्रकृति रही है। इससे हमारी पहचान राजनीतिक दल से अधिक राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्र समर्पित भावना के विस्तार के आंदोलन के रूप में बनी है। इसकी भूमिका राष्ट्रीय अभ्युदय अनुष्ठान के रूप में परिभाषित हुई है। प्रारंभिक रूप से ही सेवा के संस्कार को संगठन के श्रृंगार के रूप में आत्मसात किया है। मध्यप्रदेश में राष्ट्रवाद के प्रवर्तन में 1951 के दशक से ही जो बयार बही, उससे शहरी अंचल और ग्रामीण प्रांतर सुरभित हुए हैं और देश में मध्यप्रदेश को एक आदर्श (मॉडल) संगठन के रूप में लोकप्रियता हासिल हुई है। मध्यप्रदेश में संगठन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं में न तो स्पर्धा हुई और न अभाव दृष्टि गोचर हुआ। कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों में जहां विचारधारा गौण बनी और अवसरवादिता और सत्ता लिप्सा का प्राधान्य हुआ, जनसंघ और भाजपा में परिवार भावना में लोकतंत्रीय भावना से संस्कार जनित उत्तराधिकार मिला। सामान्य कार्यकर्ता को संगठन के नेतृत्व और सत्ता के सूत्र संभालने का गौरव प्राप्त होना यहां आकस्मिकता नहीं सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। नवम्बर 2006 में पार्टी का नेतृत्व जब नरेन्द्र सिंह को सौंपा गया सर्व सम्मति से हुए निर्णय को स्वीकार करते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रदेश के मंत्रिमंडल से तत्काल त्यागपत्र देकर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया। संगठन के श्रेष्ठि वर्ग के आदेश को शिरोधार्य किया। सत्ता और संगठन में नरेन्द्र सिंह तोमर ने संगठन के संवर्धन, जनता की सेवा का पथ चुन कर ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जो आने वाले समय में पथ प्रदर्शन करेगा।

प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर का कार्यकाल वास्तव में अवसर और चुनौतियों, संघर्ष और सेवा का ऐसा संगम है, जिसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, संगठन और सत्ता के समन्वय ने स्मरणीय बना दिया। मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर की उक्ति को उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया। विधानसभा के उपचुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बावजूद पार्टी संगठन ने रचनात्मक और संगठनात्मक गतिविधियों की अविरल धारा प्रवाहित की। कई मिथक तोड़े। नये–नये कीर्तिमान गढ़े और सेवा के नये नये अनुष्ठान लेकर सतत जनता से संवाद बनाए रखा। यही कारण था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ। पार्टी की पिछली तीन सरकारें अल्पजीवी रही। प्रदेश में दूसरी बार भाजपा शानदार विजय के साथ सत्ता में लौटी और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। चुनावी अश्वमेघ का घोड़ा कांग्रेस को नगरीय निकायों के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी रौंधता हुआ आगे बढ़ा। तथापि संगठन और कार्यकर्ता न तो आत्ममुग्ध हुए और न आत्मश्लाधा के वशीभूत हुए। पल–पल सेवा संस्कार की सतत यात्रा में संलग्न है। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अजेय और सेवान्मुख होने के साथ सबसे बड़े, व्यापक जनाधार वाली पार्टी बनी है।

नरेन्द्र सिंह तोमर ने संगठन सूत्र संभालते ही हर कार्यकर्ता को काम और हर व्यक्ति को संस्कार देने की रचनात्मक पहल की जिससे प्रदेश स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक संवाद और विश्वास का सेतु बना। कार्यकर्ता सत्ता के पूरक बने। सेवोन्मुख कार्यकर्ताओं ने हमेशा सरकार को जनता की नब्ज की जानकारी देकर शासन का अधिक संवेदनशील बनाया। नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं की प्रतिभा को निखारा और उनकी रचनात्मक ऊर्जा को दिशा दी। लोकतंत्र की बहाली में जिन कार्यकर्ताओं ने मीसाबंदी बन कर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनका अभिनंदन किया गया। उनके त्याग, तपस्या और पीड़ा का सम्मान कराया गया। लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि से उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने के लिए जिलों में अभ्यास वर्ग, प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ता सम्मेलनों का सिलसिला अनवरत जारी रहा। विधानसभा चुनावों की दृष्टि से ये सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र स्तर तक सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

प्रदेश में छब्बीस मोर्चा और प्रकोष्ठों के गठन के साथ समाज के हर वर्ग में पार्टी का विस्तार कर संगठन को सर्वस्पर्शी , सर्वव्यापी बनाया गया। मोर्चा और प्रकोष्ठ जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति तत्पर रहे। केन्द्र सरकार की विफलता को सतत बेनकाब करने में इनकी असरदार भूमिका रही। महंगायी के विरोध में सड़क से संसद तक केन्द्र सरकार की अदूरदर्शी नीतियों का आंदोलनों के माध्यम से पर्दाफाश किया गया। आंदोलनों में जनभागीदारी सुनिश्चित की गयी। प्रदेश में सांसदों और विधायकों का इंदौर में आयोजित अभ्यास वर्ग अत्यंत सफल रहा। प्रदेश के युवकों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के लिए अलग अभ्यास वर्ग चित्रकूट के आध्यात्मिक और ग्रामीण परिवेश में संपन्न हुआ, वहीं युवा मोर्चा ने जिले जिले में युवा संसद के सत्र आयोजित कर दोहरा लक्ष्यपूर्ण किया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जन–जन तक पहुंचायी। युवा नीति पर मंथन हुआ। युवा आंकाक्षा को अभिव्यक्ति मिली। यूपीए की विफलताओं की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। असंगठित कामगार प्रकोष्ठ ने प्रदेश के असंगठित मजदूरों को दिये गये राय सरकार के सुरक्षा कवच का लाभ पहुंचाया, वहीं उन्हें अपने अधिकारों से वाकिफ कराया। किसान मोर्चा ने मध्यप्रदेश में किसानी को लाभ का धंधा बनाने की राय सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान और मुख्यमंत्री के सात संकल्पों को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया। ये सात संकल्प क्रमशः 1. प्रदेश अधोसंरचना विकास। 2. निवेश में वृद्धि

से संतुलित विकास। 3. खेती को लाभ का धंधा बनाना। 4. शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जन–जन तक पहुंचाना। 5. महिला सशक्तिकरण। 6. सुशासन और संसाधनों का विकास और 7. प्रदेश में कानून व्यवस्था को चौकस बनाकर आम आदमी में सुरक्षा का अहसास पैदा करना है। मध्यप्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की 'मध्यप्रदेश बनाओ' यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। गांव–गांव में कार्यकर्ता स्वर्णिम मध्यप्रदेश की कल्पना में यथार्थ का रंग भर रहे हैं। प्रदेश सरकार की जनोन्मुखी गतिविधियों की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने के लिए विकास शिविर लगाये गये। विकास यात्राएं निकाली गयी। साथ ही जन–जन तक पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेने और काम के आधार पर समर्थन देने का आह्वान करने के लिए आशीर्वाद रैलियों, यात्राओं का जनपदीय अंचलों तक आयोजन किया गया। इनमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री तक की भागीदारी हुई।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 13–14 सितम्बर 2007 में भोपाल में संयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों और रायों से आए अतिथि से प्रदेश के कार्यकर्ताओं का जीवंत संवाद हुआ। इसका समापन विशाल जनसभा के रूप में लाल परेड ग्राउंड भोपाल पर हुआ जिसे माननीय आडवाणी जी, सुषमा स्वराज, डॉ.मुरली मनोहर जोशी, वैकेंया नायडू सहित शीर्ष नेताओं ने संबोधित कर प्रदेश की जनता के उत्साह की भूरि–भूरि सराहना की। सभा में उमड़े जन सैलाब को देखकर अतिथि प्रभावित हुए। प्रदेश में संगठन और सत्ता के समन्वय हेतु अनौपचारिक बैठकों के अलावा अन्य बैठकों के क्रम में विशेष बैठक 3 अक्टूबर 2007 को भोपाल में हुई जो विस्तारपूर्वक चर्चा के साथ संपन्न हुई। विजय संकल्प यात्रा को 6 जनवरी, 2008 में आडवाणीजी ने संबोधित किया। अमरनाथ यात्रा के लिए आवंटित जमीन पर जब रोक लगी और रामसेतु मुद्दा उठा, प्रदेश भर में आंदोलन हुए। इससे प्रदेश का कोना–कोना राष्ट्रवाद की भावना से आप्लावित हुआ। प्रदेश संगठन को अनेकों बार विधानसभा चुनावों की चुनौती से रू–ब–रू होना पड़ा। पंधाना उप चुनाव में विजयी होने के बाद लॉजी उपचुनाव सहित अन्य उप चुनावों से निपटना पड़ा। सांवेर में पिछड़ गए तो इंदौर में जीत का सेहरा बंधा। तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर) उपचुनाव में पार्टी ने कांग्रेस के कब्जे से सीट छीन कर पार्टी के बढ़ते प्रभाव सरकार की नीतियों के सुफल का परिचय मिला। महिला मोर्चा ने महंगायी के विरोध में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनायी, वहीं ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ ने अपना गांव कार्यक्रम हाथ में लेकर गांवों के विकास में नया पृष्ठ जोड़ा। अनुसूचित जाति मोर्चा ने केन्द्र सरकार की तुष्टीकरण की नीति के विरोध में जिले से लेकर दिल्ली तक विरोध का डंका बजाया और धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति कोटा में शामिल करने का विरोध किया। अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण के लिए अभियान जारी है। इसमें रंगनाथ मिश्र आयोग पर अंगुली उठायी गयी। अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने गांव–गांव में वन भूमि अधिकार पत्र वितरण में सक्रिय योगदान दिया। अल्पसंख्यक मोर्चा ने सच्चर कमेटी को तुष्टीकरण का भौड़ी मिसाल बताया और कहा कि यह मुसलमानों के स्वाभिमान पर प्रहार है। अल्पसंख्यक मोर्चा की पर्दानशीन महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और सच्चर कमेटी का पुतला जलाया। केन्द्र सरकार की मध्यप्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में लगातार आवाज उठायी गयी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जहां न्याय यात्रा निकाली, वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में सागर सहित अन्य स्थानों पर प्रभावी अनशन, आंदोलन हुए, जिनमें भारी संख्या में जनता जुटी। नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार के विरोध में सांसदों, विधायकों के धरना, आंदोलन का नेतृत्व कर जन भावनाओं को प्रति बिंवित किया। बुंदेलखण्ड में पहला मेडीकल कालेज खोला गया। लेकिन मान्यता के लिए फिर नरेन्द्र सिंह तोमर को मेडीकल कौसिंल आफ इंडिया परिसर में धरना पर बैठना पड़ा। प्रदेश में संगठन के संयोजन में कुछ रचनात्मक ऐसे कार्य हुए जिनकी देश भर में चर्चा हुई। पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे प्रशिक्षण संस्थान परिसर की आधारशिला रखी गयी। न्यास के गठन के साथ वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी ने परिसर में भव्य भवन के निर्माण का रूपांकन तैयार कर निर्माण का श्रीगणेश कराया। वैकेया नाायडू ने नींव रखी। कार्य प्रगति पर है। तीन वर्षों की कालावधि में लगातार प्रशिक्षण का क्रम इस तरह चला कि संगठन मंत्रियों से लेकर स्थानीय इकाई के कार्यकर्ता भी संस्कार संपन्न होने का गौरव प्राप्त कर सके। किसान मोर्चा ने केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का प्रखर विरोध किया और प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया। विधि प्रकोष्ठ ने विधिक साक्षरता अभियान आयोजित करने में सफलता पायी वहीं, आईटी प्रकोष्ठ ने सूचना प्रौद्योगिकी का ताना–बाना बुना। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा जोड़ो अभियान के साथ नव मतदाता सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित कर जनाधार में वृद्धि की। महिला मोर्चा ने कारवां कार्यक्रम से महिला बहनों को पार्टी के अंचल में लाने का विलक्षण अभियान चलाया जिसका लाभ हुआ। अध्यापक प्रकोष्ठ मंडल स्तर तक अपना संगठन खड़ा करने में सफल हुआ। संचार माध्यमों से बेहतर तालमेल बनाने के लिए प्रदेश के जिला, संभाग मीडिया प्रभारियों की कार्यशाला, प्रशिक्षण और

मध्यप्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की 'मध्यप्रदेश बनाओ' यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। गांव–गांव में कार्यकर्ता स्वर्णिम मध्यप्रदेश की कल्पना में यथार्थ का रंग भर रहे हैं। प्रदेश सरकार की जनोन्मुखी गतिविधियों की जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने के लिए विकास शिविर लगाये गये। विकास यात्राएं निकाली गयी।

अभ्यास वर्ग में कलमकारों को पार्टी की मूल्य आधारित नीतियों विचार दर्शन की जानकारी दी गयी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ 25 सितम्बर 2008 को जब जंबुरी मैदान भोपाल में आयोजित किया गया, उसमें उमड़े जनसैलाब ने ही विधानसभा चुनाव परिणाम की इबारत का अहसास करा दिया। मध्यप्रदेश में मतदान केन्द्र तक गठित समितियों के साथ पालक, संयोजकों के सम्मेलनों ने मतदाताओं से जोड़ दिया और ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ कि प्रदेश का प्रत्येक मतदान केन्द्र दिल्ली में बैठे जिज्ञासु की नजर में आ गया। स्विस बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए युवा मोर्चा ने जनमत संग्रह कराया। सहकारिता प्रकोष्ठ ने सहकारी क्षेत्र में साख को आसान बनाने 3 रु. प्रतिशत ब्याज पर किसानों को कर्ज दिलाने का पथ प्रशस्त किया जिससे मुख्यमंत्री के सात सूत्रीय संकल्प को बल मिला। सहकारिता आंदोलन में लोकतंत्र और शुचिता की वापसी की गयी।

प्रदेश में सदस्यता अभियान की सफलता ने अन्य प्रदेशों को चकित किया। आजीवन सहयोग निधि संग्रह में प्रदेश में नया कीर्तिमान बनाया गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ ने प्रदेश में प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टरों का महाकुंभ आयोजित कर उन्हें पार्टी की विचारधारा से परिचित कराने में सफलता प्राप्त की। नगर निगम प्रकोष्ठ नगरपालिका प्रकोष्ठ भी पीछे नहीं रहे। प्रदेश में नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्षों और पार्षदों के महासम्मेलन में प्रदेश के नगरीय विकास का खाका तैयार किया गया। भाजपा संसदीय दल के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शुचिता लाकर नगरीय निकाय को नये क्षितिज पर पहुंचाने का आह्वान किया। नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश में पहली बार अल्पसंख्यक परिवारों में से 82 प्रत्याशी जीत कर पार्षद बने। इनमें अधिकांश पर्दानशीन महिलाएं हैं। नरेन्द्र सिंह तोमर ने उन्हें बधायी देते हुए आशा व्यक्त की कि यही रफ्तार जारी रखी जावेगी और आने वाले दिनों में जारी रही तो विधानसभा परिसर में भी प्रदेश में अच्छी संख्या में अल्पसंख्यक भाई और बहनें दस्तक देंगी और विधायिका में अपना योगदान दर्ज करेगी। ■

उत्तर प्रदेश

महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी भाजपा

लगातार बढ़ रही महंगाई व केन्द्र तथा राज्य सरकार की जन विरोधी नितियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यव्यापी प्रदर्शन में महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर एकत्र हुए और मानव श्रृंखला बना प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद प्रदेश कार्यालय पर हुई सभा को प्रदेश अध्यक्ष श्री रमापति त्रिपाठी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। त्रिपाठी ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते जनता को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बीते चार माह मे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में लगभग दुगना इजाफा हुआ।

केन्द्रीय कृषि मंत्री जनता को महंगाई से निजात दिलाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए वहीं प्रधान मंत्री जोकि स्वयं एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी महंगाई पर कृषि मंत्री से बात करना उचित नहीं समझा। जहां केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में महंगाई के लिए राज्य सरकार को दोषी मानती है वहीं राज्य सरकार केन्द्र पर आरोप मढ़कर किनारा करना चाहती है जिसका खमियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है।

भाजपा जनता के शोषण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी क्रम में हाई कमान के निर्देश पर भाजपा ने प्रदेश में सड़क पर उतरने का अभियान शुरू किया जिसके अंतर्गत आज राजधानी में भाजपाइयों ने प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को चेतावनी दी कि जल्द महंगाई पर अंकुश लगाया जाए नहीं तो भाजपा अपने आंदोलन को और भी उग्र करेगी। प्रदर्शन में मुख्य रूप से विधायक, मध्य क्षेत्र सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, कैन्ट विधायक सुरेश तिवारी, पूर्वी क्षेत्र विधायक विद्या सागर गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। ■

शिवशक्ति को पीएच.डी. उपाधि

कमल संदेश संपादक मंडल सदस्य श्री शिवशक्ति बख्शी को देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएच.डी. उपाधि से विभूषित किया है। उनके शोध का विषय ''ए हिस्ट्री ऑफ कानसीयन्स एण्ड मेन्टालिटी ऑफ मिशनरीज एण्ड कान्वर्टस 1800–1950'' था। श्री शिवशक्ति झारखण्ड के गिरीडीह जिले के रहने वाले हैं। वे पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अभाविप अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश विद्यार्थी परिषद सहमंत्री तथा अभाविप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनेक वर्षों तक सदस्य रहे हैं। वह शिक्षा बचाओ आंदोलन के केन्द्रीय समिति सदस्य भी रहे हैं। 'कमल संदेश' संपादक तथा राज्य सभा सदस्य श्री प्रभात झा तथा सम्पादक मंडल के अन्य सदस्यों ने श्री शिवशक्ति को बधाई दी है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।